04 - युद्ध, बुद्ध, समाजवाद, सेक्युलरिज्म की छाया में बिहार चुनाव

05 - 38 प्रतिशत आंगनवाड़ियों में बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार

A Daily News Magazine

इंदौर

मंगलवार, 08 जुलाई, 2025

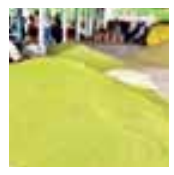
06 - जिले में खरीदी के लिए बनाए है 20 केन्द्र, बारिश ने भी किसानों को रोका रास्ता

07 - केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज की अध्यक्षता में आईसीएआर की...

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 10 अंक 269, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

पता नहीं
क्या हो गया
जीवन बाज़ार हो गया है

पता नहीं
क्या हो गया
मौत जीवन के घर
आ गई है

पता नहीं
क्या हो गया
आदमी हैवान
होता जा रहा है

पता नहीं
क्या हो गया
झूठ सिंहासन पर
आसीन हो गया है

पता नहीं
क्या हो गया है
संस्कृति को हत्यारे
छीन ले गये हैं।

-दुर्गाप्रसाद झाला

प्रसंगवश

बिहार: पासवान के बोल सिर्फ बयान या भावी राजनीति का संकेत ?

संतोष कुमार पाठक

बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव से लेकर विपक्षी गठबंधन में शामिल तमाम राजनीतिक दल राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की जनता को लालू यादव-राबड़ी देवी के जंगलराज की लगातार याद दिला रहे जेडीयू और भाजपा के नेता सरकार के पक्ष में तर्क दे रहे हैं।

लेकिन एनडीए गठबंधन में शामिल और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान के बयान ने एनडीए गठबंधन में खासकर जेडीयू नेताओं में खलबली मचा दी है। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के मुखिया एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की राजधानी पटना के पॉश इलाके में एक बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर अपनी ही गठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने बहुत ही तल्ख अंदाज में इस हत्या को चिंताजनक बताते हुए कहा कि यह हत्याकांड इस बात का संकेत है कि बिहार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। चिराग की पार्टी ने उनके बयान के वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। चिराग ने नीतीश सरकार पर सीधा-सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़ा है और कानून-व्यवस्था जिस तरह से ध्वस्त हुई है, यह चिंता का विषय है। मैं केवल एक व्यापारी की हत्या को लेकर नहीं कह रहा हूं हालांकि यह भी चिंता का विषय है क्योंकि ऐसी जगह पर यह घटना घटी है जो पटना का एक पॉश इलाका है। 100 मीटर की दूरी पर जहां थाना है और अधिकारियों के घर हैं। यदि यहां पर ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव-देहात में क्या हो रहा होगा? अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। कहां चूक हुई है, इसे हमें सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके हमें एक उदाहरण देना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे।' चिराग पासवान का यह बयान विपक्षी नेताओं के बयानों को और ज्यादा मजबूती देता हुआ नजर आता है कि लालू-राबड़ी के जंगलराज की बात करने वाले नीतीश कुमार बिहार की कानून व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं,अपराधी बेखौफ हो चुके हैं और सुशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है।

ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि आखिर केंद्र सरकार में मंत्री चिराग पासवान के बयान के मायने क्या है ? वह चाहते क्या हैं ? यह कोई पहला मौका नहीं है जब चिराग पासवान ने अपने बयान से बिहार की नीतीश सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा की हो। इससे पहले भी वो लगातार कई मौकों पर बिहार की कानून व्यवस्था को ध्वस्त बता चुके हैं।

बिहार में इसी वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर भी चिराग पासवान ने एनडीए गठबंधन के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर रखी है। एक तरफ वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर सीट बंटवारे को लेकर हुई बैठक में शामिल होते हैं, लगातार एनडीए गठबंधन को चुनाव में विजयी बनाने की बात करते हैं, बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं होने की बात कहते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं।

चिराग पासवान के विरोधाभासी बयानों ने बिहार की राजनीति को उलझा दिया है। जरा उनके और उनके बहनोई एवं लोकसभा सांसद अरुण भारती के कुछ बयानों पर नजर डालिए। एक तरफ जहां चिराग कह रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है तो दूसरी तरफ वह खुद विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। इतना ही नहीं वह बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए बिहार जाने की बात कर रहे हैं। छपरा में एक बार फिर उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात को दोहराते हुए कहा कि, 'आज सारण की इस पावन धरती से, आप सबके सामने मैं यह कहकर जा रहा हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो सही मायनों में प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएगा।' इससे पहले उनके बहनोई एवं लोकसभा सांसद अरुण भारती एक वीडियो जारी कर चिराग पासवान के शाहाबाद क्षेत्र से चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। अरुण भारती को चिराग पासवान ने पार्टी का चीफ व्हिप भी बनाया हुआ है और वह लगातार यह भी बयान दे रहे हैं कि बिहार चिराग पासवान को बुला रहा है। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो रहा है कि अगर बिहार एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान को बुला रहा है (बकौल लोजपा नेता) तो फिर नीतीश कुमार कहां जाएंगे? और अगर बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है (जैसा कि चिराग पासवान ने स्वयं कई बार कहा है) तो क्या वह केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री का पद और सांसदी सिर्फ एक विधायक बनने के लिए छोड़ेंगे? उनकी पार्टी को एनडीए गठबंधन में किसी भी सूरत में 30 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने वाली है, यह जानने के बावजूद एक तरफ जहां चिराग पासवान बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने का दावा कर रहे हैं तो साथ ही एनडीए गठबंधन को जीत दिलाने की भी बात कह रहे हैं।

साफ जाहिर हो रहा है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर या तो स्वयं कंफ्यूज हैं या फिर अंतिम समय तक बीजेपी और जेडीयू को दुविधा में रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर गठबंधन में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए वह इस तरह का विरोधाभासी बयान दे रहे हैं तो फिर लॉन्ग टर्म में इसका खामियाजा उन्हें ही उठाना पड़ सकता है। लेकिन चिराग ने अपने बयानों से बिहार में ऐसे हालात जरूर पैदा कर दिए हैं कि उनके सहयोगी उन्हें शंका और विरोधी उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं।

(प्रभासाक्षी डॉट कॉम पर प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत, सुविधा नहीं : मोदी

पीएम बोले-पहलगाम आतंकी हमला पूरी इंसानियत पर चोट

रियो डी जनेरियो (एजेंसी)। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में रविवार को हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट वाला एक जॉइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजराइली हमले की निंदा की गई। इससे पहले 1 जुलाई को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वाले क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समिट में कहा कि पहलगाम आतंकी हमला सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत पर चोट है। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। पीएम ने कहा, 20वीं सदी में बनाई गईं वैश्विक संस्थाएं 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम हैं। एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्थान 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होता। 20वीं सदी के

- **ट्रम्प की धमकी-नए देश ब्रिक्स से जुड़े तो उन पर एक्स्ट्रा टैरिफ**

टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स से जुड़ने की इच्छा रखने वाले नए देशों पर एक्स्ट्रा 10 फीसदी टैरिफ का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों की अलग-अलग

सोच और बहुध्रुवीय दुनिया में भरोसा ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि बैंक को सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना चाहिए जो जरूरी हों, लंबे समय तक फायदे वाले हों और जिससे बैंक की साख बनी रहे। पीएम मोदी ने एक ऐसा ब्रिक्स रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव रखा, जहां सब देश मिलकर विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर काम कर सकें। मोदी ने कहा कि किसी देश को यह हक नहीं कि वो किसी भी संसाधन को सिर्फ अपने फायदे के लिए या हथियार की तरह इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे पता चले कि कोई डिजिटल जानकारी असली है या नहीं, वो कहां से आई, और उसका गलत इस्तेमाल न हो। पीएम मोदी ने बताया कि भारत जल्द ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (एआई) पर एक बड़ा सम्मेलन करेगा, जिसमें इसकी चुनौतियों और अच्छे उपयोग पर चर्चा होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ब्रिक्स से जुड़ने वाले देशों को धमकी दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि जो भी देश अमेरिका विरोधी ब्रिक्स नीतियों के साथ खुद को जोड़ेंगे, उन पर 10 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।

पंजाब और मध्यप्रदेश मिलकर करेंगे देश का विकास

लुधियाना इंटरैक्टिव सेशन में मिले 15,606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि देश का आर्थिक तंत्र मजबूत हुआ है। देश में औद्योगीकरण बढ़ा है, अब हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। लुधियाना भारत का मैन्चेस्टर है। यहां के उद्योगपतियों ने बड़ी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लुधियाना में निर्मित ए-वन और हीरो साइकिल्स देश-दुनिया में मशहूर हैं। पंजाब के निवेशक देश की आर्थिक समृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख ध्वजवाहक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज लुधियाना में हुये इंटरैक्टिव सेशन, वन-टू-वन चर्चा और संवाद सत्रों में यहां के उद्योगपतियों से 15 हजार 606 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जिससे 20 हजार से अधिक रोजगार का सृजन होगा। हमने

लुधियाना और पंजाब के उद्योपतियोंत को मध्यप्रदेश में उद्योग लगाने के लिये आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें मध्यप्रदेश में उपलब्ध संसाधनों के साथ राज्य की औद्योगिक नीतियों से भी अवगत कराया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सोमवार को पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना में मध्यप्रदेश में निहित निवेश की संभावनाओं के संबंध में निवेशकों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पंजाब के लुधियाना में मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर इंटरैक्टिव सत्र का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

मैं डबल रोल में हूं, एमपी और पंजाब बिछड़े हुए सगे भाई, आप इंडस्ट्री लगाएं, लेबर को हम 5 हजार देंगे

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को पंजाब के लुधियाना में उद्योगपतियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कहा- वैसे मेरा डबल रोल है। मप्र के उद्योग मंत्री का काम भी मेरे पास है और मुख्यमंत्री भी मैं ही हूं। ये आप सभी से सरलता से बात करने के लिए ही है। सीएम ने कहा- आप एमपी में रेडिमेड गारमेंट की इंडस्ट्री लगाएंगे तो लेबर आपके यहां काम करेगी। प्रॉफिट आपको मिलेगा, लेकिन लेबर को प्रति व्यक्ति 5 हजार रुपया भुगतान हम देंगे। रोजगारपरक इंडस्ट्रीज की अपनी कठिनाइयां होती हैं, इसलिए उनको मदद कर रहे हैं। जमीन पानी, ब्याज बिजली और चीजों में तो मदद करेंगे ही।

बिहार के पूर्णिया में परिवार के 5 लोगों की हत्या

- **डायन बताकर सभी को पीट-पीटकर मार डाला**

पूर्णिया (एजेंसी)। बिहार के पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की गई है। रविवार रात से सभी लापता थे। सोमवार शाम को सभी की बॉडी मिली है। लाशें घर से डेढ़ किलोमीटर दूर तालाब में मिलीं। जिन्हें जलाने के बाद अलग-अलग बोरों में भरकर जलकुंभियों के बीच छिपाया गया था। सभी शव 80 फीसदी से ज्यादा जल चुके हैं। मृतकों में बाबू लाल उरांव, उनकी पत्नी, मां, बहू और बेटा शामिल है। पुलिस के अनुसार, परिवार झाड़फूंक करता था। 3 दिन पहले गांव में एक बच्चे की मौत हो गई। गांव वालों ने अंधविश्वास में इस हत्याकांड को अंजाम दिया। बाबूलाल के बेटे सोनू ने बताया कि मेरे सामने ही पूरे परिवार को मारा गया है। रविवार की रात 10 बजे अचानक 50 लोग घर पर आ गए और मेरी मां सीता देवी को डायन बताकर बांस के पीटने लगे। उन लोगों ने मेरे परिवार को पीट-पीटकर मार डाला। पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी नकुल ने कहा- मारपीट के बाद डीजल छिड़ककर पांचों को जिंदा जलाया था।

शुभांशु ने अंतरिक्ष से वीडियो कॉल पर दिखाया सूर्योदय

- **20 मिनट में दोपहर हो गई, लखनऊ में मां बोलीं-वो नजारा हमारे लिए चमत्कार था**

लखनऊ (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लखनऊ में रहने वाले अपने परिवार से सैटेलाइट के जरिए बात की। स्पेस स्टेशन का सीन दिखाया। इस दौरान वहां हुए सूर्योदय को भी दिखाया। घरवालों से बात करते-करते वहां 20 मिनट में दोपहर हो गई। ऐसा देखते हुए उनके घरवाले रोमांचित होते रहे। शुभांशु ने घरवालों को बताया कि शुरुआत के 3 दिन सिर में भारीपन और असहजता महसूस हुई। लेकिन, अब खुद को वहां के माहौल में ढाल चुके हैं। खुद को बांधकर कभी छत, तो कभी दीवार से चिपककर सोते हैं। सोते कहीं और हैं और जगते कहीं और हैं। जो टारगेट उन्हें मिला है, वह समय पर पूरा हो जाएगा। शुभांशु के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने बताया- करीब 15 मिनट तक हमारी वीडियो कॉल हुई। पूरा परिवार जुड़ा था। शुभांशु ने हमें अपने स्टेशन की लैब, सोने की जगह, काम करने की तकनीक और डाइनिंग सेटअप तक सब कुछ दिखाया। उन्होंने आगे कहा- हमने पूछा कि आप सोते कैसे हो तो शुभांशु ने बताया कि हम लोग खुद को बेल्ट से बांध लेते हैं, वर्ना फ्लोट करने लगते हैं। उन्होंने सूर्योदय का नजारा भी दिखाया, जो बेहद शानदार था। अपने मिशन की प्रगति, लैब में हो रहे रिसर्च और दैनिक गतिविधियों की जानकारी भी दी। शुभांशु की मां आशा शुक्ला ने कहा- हम सभी बहुत भावुक हो गए, जब शुभांशु ने हमें वहां की दुनिया दिखाई। शुभांशु ने बताया कि कैसे शुरू में उसे सिरदर्द हुआ, लेकिन अब सब ठीक है। स्लीपिंग बैग, खाने का तरीका, सूर्योदय और स्टेशन के हर हिस्से का परिचय करवाया। हमने पूछा कि वहां नींद कैसे आती है तो उन्होंने कहा कि कोई दीवार से चिपककर सोता है, कोई छत से। सोने की कोई तय जगह नहीं है। खाने का स्वाद नहीं है, लेकिन उसमें जरूरी पोषक तत्व होते हैं। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हमने ऐसे नजारे देखे, जो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। शुभांशु की बहन शुचि मिश्रा कहती हैं- भइया बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने पूरे स्टेशन का 'टूर' करवा दिया। जिस समय हमारी बातचीत हो रही थी, उसी वक्त वहां सूर्योदय हुआ। हमें पृथ्वी का घेरा दिखा, वो नीला-सा गोल स्ट्रक्चर जिसे देखकर हम दंग रह गए।

प्रधानमंत्री से बात कर गर्व महसूस किया

घरवालों से बातचीत में शुभांशु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब देश का प्रधानमंत्री खुद आपसे बात करे, तो एक अलग ही प्रेरणा मिलती है। उनके शब्दों ने मुझे और आत्मविश्वास दिया। फिलहाल शुभांशु की पृथ्वी पर वापसी की तारीख तय नहीं हुई है। उन्होंने अपने परिवार से कहा कि वह सभी काम ध्यानपूर्वक और समय से पूरा कर रहे हैं। शुभांशु का कहना है कि वो मिशन को पूरी सफलता से खत्म करके जल्द ही लौटेंगे।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 35 °c | न्यूनतम 30°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ मंगलवार, 08 जुलाई 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

'बेल नियम है और जेल अपवाद' का रूल भुलाया गया

● सीजेआई गवई बोले-मैंने सिसोदिया केस में याद दिलाया

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई का कहना है कि 'बेल नियम है और जेल अपवाद है' यह एक वैधानिक सिद्धांत है। इसका पालन अदालतों में पिछले दिनों बंद हो गया था। चीफ जस्टिस ने केरल हाई कोर्ट में आयोजित जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर मेमोरियल लेक्चर में यह बात कही। उन्होंने कहा कि बेल नियम है और जेल अपवाद इस सिद्धांत को भुलाने की कोशिश हुई, लेकिन मैंने मनीष सिसोदिया, के. कविता और प्रबिर पुरकायस्थ मामले में इसे याद दिलाया। उन्होंने कहा, जस्टिस कृष्ण अय्यर का पूरी मजबूती से यह मानना था कि अंडरट्रायल लोगों को जेल में नहीं रखना चाहिए। बिना ट्रायल के उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना सही नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारतीय न्यायपालिका में जस्टिस कृष्ण अय्यर की पहचान लीक से हटकर काम करने की रही। उन्होंने ऐसी कई चीजों को लागू किया, जिन्हें टैबू माना जाता था। उनकी ओर से ही इस सिद्धांत पर जोर दिया गया कि बेल अधिकार है और जेल अपवाद है। पिछले कुछ समय में अदालतों ने इस सिद्धांत को भुलाने की कोशिश की। मुझे खुशी है कि बीते साल जब मुझे मौका मिला तो मैंने इस सिद्धांत को फिर से याद दिलाया। मैंने प्रबिर पुरकायस्थ, मनीष सिसोदिया और के. कविता के केस में इस सिद्धांत को याद दिलाया। इस तरह जस्टिस बीआर गवई ने जिन केसों की याद दिलाई, उनमें मनीष सिसोदिया का केस भी शामिल है। इसके अलावा के. कविता को भी दिल्ली के शराब घोटाले के केस में अरेस्ट किया गया था। इन मामलों की सुनवाई जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो बेंच का हिस्सा रहे जस्टिस गवई ने बेल के सिद्धांत की याद दिलाई। जस्टिस गवई ने कहा कि हम जब वी. आर कृष्ण अय्यर को याद करते हैं तो ध्यान आता है कि उन्होंने लैंगिक असमानता को खत्म करने वाले कदम उठाए।

पद्मनाभ मंदिर में स्मार्ट ग्लास पहनकर घुस रहा था व्यक्ति

● सुरक्षाकर्मियों ने दबोचा, चश्मे में लगे हुए थे सीक्रेट कैमरे

तिरुवनंतपुरम (एजेंसी)। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में स्मार्ट ग्लास पहनकर प्रवेश करने की कोशिश कर रहे एक शख्स को पकड़ा गया है। श्रद्धालु की पहचान 66 वर्षीय सुरेंद्र शाह के रूप में हुई है, जो मूल रूप से गुजरात का रहने वाला है। सुरेंद्र शाह को रविवार शाम मंदिर के सुरक्षाकर्मियों ने हिरासत में ले लिया। चश्मे में लगे हुए थे सीक्रेट कैमरे पुलिस के मुताबिक, मंदिर में कैमरा लगे चश्मे जैसे उपकरण प्रतिबंधित हैं। इसके बावजूद सुरेंद्र स्मार्ट ग्लास पहनकर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा था। शाह मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर में दाखिल हुआ। उसके हावभाव से सुरक्षाकर्मियों को उस पर शक हुआ और उन्होंने उसे वापस बुलाया। जांच करने पर पता चला कि उसके चश्मे में छिपे हुए कैमरे लगे थे।

एमपी से गुजरात तक बारिश-बाढ़ का कहर

शहडोल जिले में 3 हजार घरों में घुसा पानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। एमपी,राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर ओजरी इलाके में पुल बह जाने से आसपास के इलाकों का सड़क संपर्क टूट गया है। वहीं, श्रीनगर में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। आधी रात 3 हजार से ज्यादा घरों में पानी भर गया। यहां अस्पताल में पानी भर जाने पर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा। राजस्थान में भी तेज बारिश का दौर जारी है। झुंझुनूं में बाघोली नदी के तेज बहाव के चलते नेशनल हाईवे-52 को जोड़ने वाली सड़क धंस कर पानी में बह गई। सीकर में बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया। नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई के बीच बादल फटने की 19 घटनाएं हुईं। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुए।

जस्टिस वर्मा केस में तुरंत एफआईआर की है जरूरत

उपराष्ट्रपति बोले-कैश कहां से आया, ये जानना जरूरी

नई दिल्ली (एजेंसी)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को जस्टिस वर्मा के घर में मिले अधजले नोटों के मामले में तुरंत एफआईआर की बात कही। उन्होंने कहा- यह न केवल चिंताजनक है, बल्कि यह हमारी न्यायपालिका की नींव को हिला देने वाला है। इस मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है। कैश कहां से आया, ये जानना बहुत जरूरी है। केंद्र स्तर पर सरकार मजबूर है, क्योंकि 90 के दशक की शुरुआत में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण जस्टिस पर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। धनखड़ ने नेशनल एडवांस्ड लीगल स्टडीज यूनिवर्सिटी के सेमिनार में ये बातें कहीं। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। उनके घर के स्टोर रूम में 500-500 रुपए के जले नोटों के बंडलों से भरे बोरे मिले थे। इसके बाद से ये सवाल खड़ा हुआ कि इतना कैश कहां से आया। मैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन करता हूं। जजों को सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है क्योंकि वे जटिल परिस्थितियों में काम करते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो हमें सच का सामना करना होगा। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले नकदी का हवाला दिया। उन्होंने इसे शेक्सपियर के नाटक 'जूलियस सीजर' से जोड़ा और 14 मार्च (जूलियस सीजर की हत्या की तारीख) को न्यायपालिका के लिए बुरा समय बताया। उन्होंने कहा, यह नकदी कहां से आई। क्या यह काला धन है। इसका मालिक कौन है। इसकी जांच होनी चाहिए। यह एक आपराधिक कृत्य है, और इसके लिए तत्काल एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने जजों को सेवानिवृत्ति के बाद दी जाने वाली नियुक्तियों पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा लोक सेवा आयोग , नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी), को सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद नहीं मिलती। लेकिन जजों के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। उपराष्ट्रपति ने संविधान की प्रस्तावना में आपातकाल के दौरान किए गए बदलावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा,प्रस्तावना को माता-पिता की तरह समझें, जिसे बदला नहीं जा सकता। विश्व में किसी भी देश ने अपनी संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं किया। उपराष्ट्रपति ने शक्तियों के अलगाव पर जोर देते हुए कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका को एक-दूसरे के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

मैं पाकिस्तानी सेना का एजेंट मुंबई अटैक में था शामिल

● तहव्वुर राणा का सबसे बड़ा कबूलनामा, दहशत में पाक

नई दिल्ली (एजेंसी)। मुंबई में हुए 26/11 आतंकवादी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। खबर है कि एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पूछताछ में उसे पाकिस्तानी सेना का भी नाम लिया है। फिलहाल, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। राणा को हाल ही में अमेरिका से प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया था। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि एनआईए की पूछताछ में राणा ने माना है कि वह पाकिस्तानी सेना का भरोसेमंद एजेंट था। सूत्रों के अनुसार, राणा ने यह भी खुलासा किया है कि उसने दोस्त डेविड हेडली के साथ पाकिस्तान के लश्कर ए तैयबा संग कई ट्रेनिंग सेशन में भाग लिया था। उसने बताया है कि लश्कर ने मुख्य रूप से जासूसी नेटवर्क के तौर पर काम किया था। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई राणा (64) वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के मुख्य षड्यंत्रकारी डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी के करीबी सहयोगी राणा को 4 अप्रैल को अमेरिका की शीर्ष अदालत द्वारा उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ समीक्षा याचिका खारिज किए जाने के बाद भारत लाया गया था। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि राणा ने माना है कि वह हमलों के दौरान मुंबई में ही था और वह भी आतंकवादी साजिश का हिस्सा था।

दिल्ली एचसी से तुर्किए की कंपनी सेलेबी को झटका

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को तुर्किए की फर्म सेलेबी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने विमानन नियामक नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) की ओर से उसकी सुरक्षा मंजूरी को रद्द किए जाने को चुनौती दी थी। विमानन नियामक ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा के हित का हवाला दिया था। जस्टिस सचिन दत्ता ने 23 मई को फैसला सुरक्षित रखने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीसीएएस ने 15 मई को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी।

सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ याचिका की खारिज

इस फैसले से कुछ ही दिन पहले तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था और आतंकी कैंपों पर भारत के हमलों की निंदा की थी। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभिन्न एयरपोर्टों पर ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो टर्मिनल कार्यों की देखरेख करते हैं। केंद्रीय प्राधिकरण के वकील ने बीसीएएस के फैसले और कार्रवाई का बचाव करते हुए विमानन सुरक्षा के लिए अभूतपूर्व खतरे की ओर इशारा किया था। वहीं सेलेबी के वकील ने दलील दी थी कि केंद्र सरकार का कदम न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह विमान सुरक्षा नियमों के तहत प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक को याचिकाकर्ताओं को उक्त फैसले की सूचना देने के बाद उनकी बात सुननी चाहिए थी।यही नहीं महानिदेशक को इस फैसले के कारण भी बताने चाहिए थे।

सारा सामान पैक कर लिया है, रेडी टू मूव

● बंगला खाली ना करने की शिकायत पर बोले पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का सरकारी बंगला खाली न करने वाले विवाद पर जवाब आया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को इस संबंध में लिखा गया था कि पूर्व सीजेआई अपने सरकारी आवास में बने रहने की सीमा पार कर चुके हैं और बंगला खाली नहीं कर रहे हैं। उनसे बंगला तुरंत खाली कराया जाए। अब इसे लेकर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का बयान आया है। उनका कहना है कि हमारा पूरा सामान पैक है। हम जल्दी ही यहां से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम रेडी टू मूव हैं और ज्यादा से दो सप्ताह या फिर 10 दिन के अंदर घर खाली कर देंगे। उन्हें चीफ जस्टिस के तौर पर दिल्ली के कृष्ण मेनन मार्ग पर 5 नंबर बंगला मिला था। वह नवंबर 2024 में रिटायर हो गए थे और तब से अब तक इसी बंगले में रह रहे हैं। उनके रिटायरमेंट के बाद जस्टिस संजीव खन्ना मुख्य न्यायाधीश बने थे, लेकिन उन्हें सरकारी आवास नहीं लिया था।

बीजापुर में माड़वी हिडमा के राइट हैंड का एनकाउंटर

जवानों ने गढ़ में घुसकर मारा,संगठन में था स्नाइपर एक्सपर्ट

बीजापुर (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ में सुरक्षाबल के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। शनिवार को बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के दौरान मारे गए नक्सली की पहचान हो गई है। मुठभेड़ में 8 लाख का इनामी माओवादी डिप्टी कमांडर सोढ़ी कन्ना मारा गया। उसके शव के पास से जवानों को हथियार समेत विस्फोटक भी बरामद हुए थे। सोढ़ी कन्ना बटालियन नंबर 1 डेप्युटी कमांडर था। वह खूंखार नक्सली हिडमा का करीबी था। सोढ़ी कन्ना को हिडमा का राइट हैंड माना जाता था। बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र यादव ने बताया कि जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र में माओवादी कैडर की गतिविधियों की सूचना पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा 202, कोबरा 210 एवं सीआरपीएफ यंग प्लाटून की संयुक्त टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया था।

तेलंगाना धमाके में बढ़ गई है मरने वालों की संख्या

● आंकड़ा पहुंचा 42,8 लोग अब भी लापता,तलाश जारी

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना की फॉर्मा फैक्ट्री धमाके में मरने वालों का आंकड़ा 42 हो गया है। रविवार को एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई, जबकि एक शव की पहचान एनआईए जांच से हुई है। 8 लोगों लापता हैं। हादसे से 6 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने रविवार को बताया कि शनिवार और रविवार को घटनास्थल से कुछ हड्डियां और शरीर के जले अंग मिले हैं। इनका टेस्ट चल रहा है।

टेम्पो ट्रैक्स पेड़ से टकराया, 3 महिलाओं की मौत

शहडोल में बच्चों समेत 15 घायल, सभी अयोध्या से छत्तीसगढ़ लौट रहे थे

शहडोल (नप्र)। शहडोल के ब्यौहारी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह 4.40 बजे एक टेम्पो ट्रैक्स जोरा गांव के पास पेड़ से टकरा गया। हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। वहीं 15 महिलाएं और बच्चे घायल हैं।

जानकारी के मुताबिक टेम्पो ट्रैक्स (तूफान) में कुल 20 लोग सवार थे। ड्राइवर के अलावा सभी महिलाएं और बच्चे थे। ये लोग अयोध्या से दर्शन कर लौट रहे छत्तीसगढ़ लौट रहे थे।

4 घायल शहडोल मेडिकल कॉलेज रेफर- थाना प्रभारी अरुण पांडे ने बताया कि हादसे में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पहले ब्यौहारी अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज शहडोल रेफर किया गया है। मृतकों की पहचान गायत्री कवर (55), मालती पटेल (50) और इंदिरा बाई के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के परिजन को फोन पर सूचना दी है, जो ब्यौहारी के लिए रवाना हो गए हैं।

पन्ना में एम्बुलेंस-ट्रक की टक्कर में गर्भस्थ शिशु सहित महिला की मौत- पन्ना में सीमेंट से लदे ट्राले से तेज रफ्तार एम्बुलेंस टकरा गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार गर्भवती और उसके शिशु की मौत हो गई। उसका पति और 5 अन्य महिलाएं घायल हैं। पडवार गांव की रहने वाली प्रियंका प्रजापति (27) को प्रसव पीड़ा होने पर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पन्ना लाया जा रहा था।

हिंदुओं को पीटना पहलगाम आतंकी हमले जैसा

मराठी भाषा विवाद: मंत्री आशीष शेलार बोले-कुछ नेता इसका आनंद ले रहे

मुंबई (एजेंसी)। मुंबई में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले मराठी बोलने को लेकर विवाद बड़ा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। हिंदीभाषी लोगों के खिलाफ हिंसा के बीच महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने पहलगाम आतंकी हमले और मुंबई में 'हिंदुओं' की पिटाई को एक समान बताया है। शेलार ने उद्धव-राज ठाकरे का नाम न लेते हुए रविवार को कहा कि राज्य देख रहा है कि कैसे कुछ नेता 'अन्य हिंदुओं की पिटाई का आनंद ले रहे हैं।' उनकी यह टिप्पणी उस घटना के बाद आई है, जिसमें एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में मिठाई की दुकान के मालिक की मराठी न बोलने पर पिटाई कर दी थी। इसके अलावा शनिवार को मनसे कार्यकर्ताओं ने शेयर बाजार निवेशक सुशील केडिया के वर्ली स्थित दफ्तर के कांच के दरवाजे तोड़ दिए थे। केडिया ने राज ठाकरे को चुनौती देते हुए कहा था कि वे मराठी नहीं बोलेंगे। इधर, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की हालिया टिप्पणियों की आलोचना की है और उन्हें 'दादागिरी' को बढ़ावा देने वाला बताया और एमएनएस कार्यकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि लोगों को मराठी बोलने के लिए मजबूर करना गलत है। हिंसा में शामिल मनसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अठावले ने राज के रुख पर पूछा कि ऐसी घटनाओं के कारण उद्योग बंद हो जाते हैं तो क्या वे सभी को रोजगार देंगे। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ये हमला उद्धव और राज ठाकरे की संयुक्त रैली के कुछ घंटे पहले किया गया। ये हमला केडिया के 3 जुलाई की उनकी ङ्क पोस्ट के बाद हुआ। उन्होंने मनसे चीफ राज ठाकरे को टैग करते हुए लिखा था- मुंबई में 30 साल रहने के बाद भी मैं मराठी ठीक से नहीं जानता और आपके घोर दुर्व्यवहार के कारण मैंने यह संकल्प लिया है कि जब तक आप जैसे लोगों को मराठी मानुष की देखभाल करने का दिखावा करने की परमीशन नहीं दी जाती, मैं मराठी नहीं सीखूंगा।

● अठावले की मांग-एमएनएस कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो

मेडिकल कॉलेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस में एआई की मदद से फर्जी थम्ब इम्प्रेशन

नकली फैकल्टी को रेगुलर बताकर उसकी अटेंडेंस भी दर्ज करवाई

इंदौर। मेडिकल कॉलेजों को दलाली लेकर सालाना मान्यता दिलाने के मामले में सीबीआई ने इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सुरेश भदौरिया और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन व देवी अहिल्या विवि के पूर्व कुलपति डीपी सिंह को आरोपी बनाया। जांच में अब कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। फर्जी तरीके से कॉलेजों को मान्यता दिलाने और रिन्यू कराने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का मिसयूज किया गया। दरअसल, मान्यता के पैरामीटर पूरा करने के लिए फैकल्टी की नियमित उपस्थिति जरूरी है। ऐसे में इंस्पेक्शन के पूर्व फर्जी तरीके से फैकल्टी दर्शाई गई। इसके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने के लिए एआई से फर्जी थंब इंप्रेशन तैयार किए गए। इसके बाद फैकल्टी की नियमित उपस्थिति दिखाई गई। सीबीआई की जांच में यह बिंदु प्रमुखता से है। इसमें भदौरिया की लिप्तता के सूत्र मिले हैं।

इंस्पेक्शन की सूचना पहले मिलती - सुरेश भदौरिया के भारत सरकार के एक बड़े अधिकारी से गहरे संबंध हैं। उनके जरिए उन्हें इंस्पेक्शन कब होने वाला है, इसकी जानकारी मिल जाती थी। ऐसे में फर्जीवाड़ा की तैयारी पहले ही कर ली जाती थी। कॉलेजों में फर्जी फैकल्टीज, फर्जी मरीजों को रिकॉर्ड पर दर्शाने जैसी गड़बड़ियां भी हुई। भदौरिया पर आरोप है कि वे कॉलेजों के चेयरमैन और डायरेक्टर से तगड़ी राशि लेकर अनुकूल मान्यता दिलवाते थे। फिर भले ही पैरामीटर्स पूरे नहीं हो। केस में लिप्त देवी अहिल्या विवि के पूर्व कुलपति डीपी सिंह पर भी सीबीआई ने शिकंजा कसा है। डीपी सिंह सागर और बनारस यूनिवर्सिटी के भी वाइस चांसलर रह चुके हैं। साथ ही नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडेशन काउंसिल के डायरेक्टर भी रहे हैं। डीपी सिंह 2018 से 2021 के बीच यूजीसी के चेयरमैन रहे। उप्र सरकार में एजुकेशन एडवाइजर रहे। उनके डायरेक्टर रहते यूजीसी में भी भ्रष्टाचार हुआ जिसका सीधा फायदा कॉलेजों को मिला।

बड़ी राशि का लेन-देन- रावतपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के चेयरमैन और स्वयंभू संत रविशंकर महाराज उर्फ 'रावतपुरा सरकार' को भी इंस्पेक्शन की तारीख और अधिकारियों की जानकारी अपने खास सोर्स के माध्यम से पहले ही पता चल जाती थी। इससे फर्जीवाड़ा आसान होता गया। हालांकि, इंस्पेक्शन की तारीख के लिए तगड़ी राशि के लेन-देन होते थे। इस लेन-देन का रूप अलग होता था। यानी किसी भी बड़े धार्मिक और सोशल काम के माध्यम से किया जाता था। हवाला की राशि भी जांच के घेरे में है। पता चला है कि रावतपुरा सरकार और भदौरिया के बीच मजबूत लिंक थी।

लालबाग पैलेस को भव्य रूप देने की तैयारी, बाउंड्री वॉल और गेट बनेगा

दो दशक बाद पुनरुद्धार कार्य, पर्यटकों के लिए भी नए इंतजाम

इंदौर। लालबाग पैलेस के भव्य स्वरूप को निखारने का इंतजार अब खत्म हो गया। मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम को भोपाल से मंजूरी मिलने के बाद बाउंड्री वॉल और अन्य संरचनात्मक कार्यों की शुरुआत कर दी गई है। वर्षों से उपेक्षित इस ऐतिहासिक धरोहर को अब नई पहचान देने की तैयारी है। प्रथम चरण में करीब 8 फीट ऊंची आकर्षक बाउंड्री वॉल बनाई जा रही है, जिसमें विशेष चित्रकारी और शिल्पकारी की जाएगी। साथ ही लालबाग पैलेस के पीछे एक नया भव्य गेट बनाने की योजना भी शुरू हो गई है। इस गेट के ऊपर घोड़े की मूर्ति भी स्थापित की जाएगी, जो आने-जाने वाले पर्यटकों को शाही अनुभव देगी। अधिकारियों के अनुसार पुनरुद्धार कार्य में प्रवेश मार्ग, उद्यान और आंतरिक सौंदर्यीकरण भी शामिल हैं। पर्यटकों की सुविधा और आवागमन को ध्यान में रखते हुए मुख्य गेट के अलावा पीछे से बाहर निकलने की व्यवस्था की जा रही है।

अन्य पर्यटन स्थलों पर भी विकास- इंदौर में केवल लालबाग ही नहीं, बल्कि राजवाड़ा, गांधी हाल और कृष्णपुरा छत्रियों के संरक्षण को लेकर भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। स्मार्ट सिटी मिशन और पर्यटन विकास निगम मिलकर इन धरोहर स्थलों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। लालबाग पैलेस का पुनरुद्धार शहर के सांस्कृतिक और पर्यटन क्षेत्र को नया जीवन देगा। आने वाले समय में यह इंदौर का प्रमुख आकर्षण केंद्र बनकर उभरेगा।

बालदा कॉलोनी में संजीवनी क्लीनिक 117 जांचें, 200 दवाई मुफ्त मिलेंगी

स्वच्छ के बाद स्वस्थ इंदौर, जनभागीदारी से क्लीनिक का संचालन

इंदौर। नगर निगम इंदौर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शहर में सीएम संजीवनी क्लिनिकों की श्रृंखला लगातार विस्तार पा रही है। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र-4 के वार्ड 67 स्थित बालदा कॉलोनी में एक और संजीवनी क्लिनिक का उद्घाटन महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर विधायक मालिनी गौड़,पार्षद प्रिया डांगी, वैष्णव संस्था के पुरुषोत्तम पसारी सहित बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद रहे। महापौर भार्गव ने कहा कि स्वच्छ इंदौर के बाद अब हमारा लक्ष्य है स्वस्थ इंदौर। उन्होंने बताया कि शहर में 105 से अधिक संजीवनी क्लिनिक बनाए जा रहे हैं। जिनमें से 72 से अधिक तैयार हो चुके। अब जनसहयोग से इनके संचालन का कार्य प्रारंभ हो गया है। इंदौर देश का पहला शहर बन गया, जहां जनभागीदारी से स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिसमें 117 प्रकार की जांचें और 200 से अधिक दवाएं निःशुल्क दी जा रही हैं। विधायक मालिनी गौड़ ने कहा कि यह क्लिनिक वार्ड 67 के लिए एक बड़ी सौगात है और स्थानीय नागरिकों को अब प्राथमिक उपचार के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।

चोरी की वारदातें बढ़ीं, बाइक उड़ाई

इंदौर। शहर में लगातार चोरी की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। ताजा मामला एमआईजी थाना क्षेत्र के नेहरू नगर रोड नंबर 3 का है, जहां एक युवक की बाइक अज्ञात बदमाश चुरा ले गए। जानकारी के अनुसार, नितेश चौहान की बाइक (क्रमांक एमपी-11-एनए-4654) उनके घर के सामने खड़ी थी। सुबह जब उन्होंने बाहर देखा तो बाइक गायब थी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की, जिसमें सुबह 5 बजे के करीब तीन बदमाश तीन अलग-अलग बाइकों से आते हुए और नितेश की बाइक चुराकर ले जाते हुए दिखाई दिए। एमआईजी थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है और बदमाशों की पहचान व तलाश शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरी की वारदातों से क्षेत्र के नागरिकों में भय का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

नारायण बाग से निकली आषाढ़ी एकादशी की भव्य दिंडी यात्रा

इंदौर। आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर नारायण बाग दत्त मंदिर से भव्य दिंडी यात्रा का आयोजन हुआ, जो शहर की भक्ति परंपरा और वारकरी संस्कृति का जीवंत प्रतीक बनी। यह यात्रा नारायण बाग से प्रारंभ होकर पंत वैद्य कॉलोनी, जति कॉलोनी और रामबाग होते हुए मल्हारी मार्तंड मंदिर, तिलक पथ पर समापन तक भाव-विभोर वातावरण में सम्पन्न हुई। वारकरी संप्रदाय की परंपरा के अनुसार, दिंडी यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवा ध्वज, मृदंग, झांझ और टाल के साथ 'जय जय रामकृष्ण हरी' और संत तुकाराम-मुक्ताबाई के अभंगों का गान करते हुए भाग लिया। यात्रा में संतों की उपस्थिति ने माहौल को अलौकिक बना दिया। इस अवसर पर विधायक गोलू शुक्ला, पार्टी के पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, भजन मंडलों के सदस्य, महिला मंडल, युवा कार्यकर्ता एवं सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिंडी यात्रा को व्यवस्थित और भव्य बनाने में क्षेत्रीय पार्षद सुरेश टाकलकर और झोन अध्यक्ष पार्षद गजानन गावडे का भी सक्रिय सहयोग रहा। दिंडी का समापन मल्हारी मार्तंड मंदिर पर आरती व प्रसाद वितरण के साथ संपन्न हुआ। पार्षद सुरेश टाकलकर ने बताया कि यह दिंडी यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, अपितु समाज की आध्यात्मिक एकता, लोक संस्कृति और संत परंपरा का सजीव उत्सव बनकर उभरी।

आई अस्पताल के डायरेक्टर दंपत्ति ने इस्तीफा दिया

इंदौर। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई के डायरेक्टर डॉ. प्रतीप व्यास और उनकी पत्नी डॉ. शरादिनी व्यास ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने ईमेल के जरिए इस्तीफा भेजा। बताया जा रहा है कि उन्हें कॉलेज प्रबंधन और स्टाफ से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा था। उपकरणों की कमी और कार्य में अड़चनों के चलते वे लंबे समय से असंतुष्ट थे। इस्तीफे के साथ ही कोर्ट से भर्ती संबंधी एक मामले में उन्हें नोटिस भी मिला है।

'कालिंदी गोल्ड' में अपराधों से रहवासी परेशान

इंदौर। शहर की कालिंदी गोल्ड कॉलोनी में नशे के कारोबार और आपराधिक गतिविधियों से परेशान होकर स्थानीय निवासियों ने अब पुलिस प्रशासन से सीधा संवाद किया है। शिवसेना महिला इकाई की जिला प्रमुख प्रियंका नामदेव ने बाणगंगा क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) को ज्ञापन सौंपते हुए कॉलोनी में स्थायी पुलिस चौकी के निर्माण की मांग की है। प्रियंका नामदेव के नेतृत्व में सौंपे गए इस ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि कॉलोनी में लगातार बाहरी असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ रहा है।

कॉलोनियों में अमानक खाद्य सामग्री बेचने वालों पर भी शिकंजा कसेगा

दूध, केमिकल से पके फल और घटिया सब्जियों की जांच होगी

इंदौर। निगरानी समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर आशीष सिंह ने सघन जांच अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बैठक में पहुंचे अधिकारियों, जागरूक उपभोक्ता समिति के पदाधिकारी और दुग्ध व्यापारी एसोसिएशन ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। मिलावटी और अमानक खाद्य सामग्री के खिलाफ शहर के व्यावसायिक क्षेत्रों में चलाई जाने वाली कार्रवाई अब कॉलोनियों में भी चलाई जाएगी। प्रशासन ने लीगल और सर्विलांस टीम सक्रिय की है, ताकि कॉलोनी में अमानक स्तर के खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर भी शिकंजा कसा जा सके। बारिश और त्योहारी मौसम के दौरान फूड पॉइजनिंग और मिलावटी सामान खाने के कारण प्रभावित हो रहे रहवासियों के बचाव के लिए जांच मोबाइल वैन पहुंचेगी और जागरूकता भी फैलाएगी। निगरानी समिति की बैठक में ग्रामीण क्षेत्र से मिलावटी दूध आने की भी शिकायत पहुंची। निर्णय के अनुसार पानी, खाद्य सामग्री, रासायनिक पदार्थ डालकर पकाए गए फलों और कीटनाशक वाली सब्जियों के प्रभाव को रोकने के लिए अब गली-गली में मोबाइल वैन पहुंचेगी। होटलों, रेहड़ी वालों द्वारा बेचे जा रहे उत्पादों के सैंपल लेकर जांच अभियान चलाएगी। अमानक स्तर का खाद्य बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों से मिलावटी दूध - इंदौर दुग्ध विक्रेता संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर को बताया कि शहरी क्षेत्र में तो फैट प्रणाली से दूध का विक्रय किया जा रहा है। लेकिन, ग्रामीण क्षेत्र के किसान दूध पर यह प्रणाली लागू नहीं करना चाहते। इस कारण अमानक स्तर का दूध शहरी क्षेत्र में भेजा जा रहा है। मिलावटी दूध की जांच की कार्रवाई में शहर के विक्रेताओं को दंड भुगतना पड़ रहा है, जबकि किसानों की तरफ से ही मिलावटी दूध की बिक्री की जा रही है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर न्यायालय ने 2023 में निर्देश जारी किए थे कि शहर के एंट्री प्वाइंट पर बूथ लगाकर उत्पादों के दूध की जांच की जाए। लेकिन, इंदौर जिले में अब तक यह प्रक्रिया लागू नहीं की गई, जबकि उज्जैन सहित 9 जिलों ने यह प्रणाली अपना ली है। वहीं एफएसएसएआई के नियमों के अनुसार उत्पादकों का रजिस्ट्रेशन भी कराया जाना चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुआ है। कलेक्टर ने जल्द ही कार्रवाई करने की बात कही।

पेट्रोल पंपों की जांच की जाएगी- पेट्रोल पंप पर मिलावटी डीजल और पेट्रोल बेचे जाने की शिकायत दर्ज कराते हुए जागरूक उपभोक्ता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इंदौर जिले के पेट्रोल पंपों पर अनियमितताओं का भंडार लगा हुआ है। शहर में एक ही ग्रेड वन फूड ऑफिसर होने के कारण पेट्रोल पंप की जांच नियमित तौर पर नहीं की जा रही है। उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाडियों में पानी मिला डीजल डालने की घटना का भी उल्लेख किया।

झुग्गी-झोपड़ी संस्था पर उठे सवाल मनमानी, जबरन वसूली के आरोप

सड़क निर्माण की खबरों के बाद मंदिर की छत पर ऑफिस

इंदौर। गांधी बेघरबार झुग्गी झोपड़ी संस्था एक बार फिर विवादों में आ गई है। संस्था ने बीते 25 वर्षों में कभी स्थायी कार्यालय नहीं बनाया,जो भी अध्यक्ष बना उसने अपने घर से ही संस्था को चलाया। लेकिन, जैसे ही मास्टर प्लान की महत्वपूर्ण सड़क एमआर-6 के निर्माण की खबरें अखबारों में छपने लगीं, वैसे ही संस्था के पदाधिकारियों ने समाजवादी इंदिरा नगर के सार्वजनिक माता मंदिर की छत पर अपना ऑफिस बना लिया। इस कदम से रहवासी नाराज हैं और इसे महज दिखावा बता रहे हैं। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि क्षेत्र में पेयजल,ड्रेनेज,सड़क और अन्य मूलभूत विकास कार्य नगर निगम द्वारा करवाए जा रहे हैं, तो फिर संस्था की कोई उपयोगिता नहीं बचती। आरोप है कि संस्था मकान बेचने या निर्माण के लिए एनओसी देने के बदले में मोटी रकम वसूलती है।

पैसे नहीं देने पर एनओसी रोक दी जाती है। कुछ जागरूक नागरिकों ने सहकारिता विभाग में शिकायत भी की,लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। रहवासियों का कहना है कि संस्था में कभी चुनाव नहीं होते, केवल एक ही परिवार वर्षों से अध्यक्ष पद पर काबिज है. पहले पिता, अब बेटा। बुजुर्ग रहवासियों ने कहा कि यह संस्था केवल दिखावे के लिए चल रही है, ताकि एमआर-6 के निर्माण में टूटने वाले 127 मकानों के एवज में फिर से कोई हेराफेरी की जा सके।

दिव्यांग छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं जांचने यूजीसी टीम डीएवीवी आएगी

120 से ज्यादा तय सुविधाओं की जांच होगी, छात्रों से भी बात करेंगे

इंदौर। यहां के देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी (डीएवीवी) के टीचिंग विभागों में दिव्यांग छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) की विशेष टीम जल्द यहां का दौरा करेगी। यह दौरा दो महीनों में दूसरी बार होने जा रहा है। टीम यूनिवर्सिटी के दोनों परिसरों तकनीकी और नालंदा कैंपस का निरीक्षण करेगी और दिव्यांग छात्रों से सीधे संवाद भी करेगी। यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार दिव्यांग छात्रों को यूनिवर्सिटी में रैंप, स्पेशल टॉयलेट, लिफ्ट, व्हील चेयर, हेल्थ सेंटर में अलग बेड, रेस्ट रूम और ग्राउंड फ्लोर पर कक्षा जैसी सुविधाएं देना अनिवार्य है। डीएवीवी में वर्तमान में 120 से अधिक दिव्यांग छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें से 50त्न सुविधाएं भी ठीक से उपलब्ध नहीं हैं।

यूजीसी की टीम यह सब जांचेगी

- यूनिवर्सिटी में व्हीलचेयर और इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं या नहीं?
- रैंप, हेल्थ डेस्क और सूचना पटल लगाए गए हैं या नहीं?
- बुक स्कैनर, प्रोजेक्शन स्क्रीन जैसी सुविधाएं मौजूद हैं या नहीं?
- इन छात्रों को ग्राउंड फ्लोर की कक्षाएं दी जा रही हैं या नहीं?
- विशेष पार्किंग और उसकी मार्किंग की गई है या नहीं?

पिछली बार मार्च में आई टीम को कई सुविधाएं दिखाई गई थीं, लेकिन अब जमीनी हकीकत जानने के लिए टीम छात्रों से सीधे बातचीत करेगी, ताकि उन्हें वास्तविक स्थिति का आकलन हो सके। इस निरीक्षण से यूनिवर्सिटी पर विकास कार्यों की पारदर्शिता और यूजीसी निर्देशों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं।

खजराना चौराहा से मंदिर मार्ग का सर्विस रोड 10 दिन में तैयार होगा

पूरा होने से जलजमाव नहीं होगा, गणेश चतुर्थी से पहले सुविधा

इंदौर। खजराना गणेश मंदिर जाने वाले भक्तों को अब जल्द ही बेहतर सुविधा मिलने वाली है। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सोमवार सुबह खजराना चौराहा से मंदिर मार्ग तक बन रहे सर्विस रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी 10 दिनों में सर्विस रोड का कार्य पूर्ण कर लिया जाए, ताकि गणेश चतुर्थी के पहले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अधीक्षण यंत्री डी.आर. लोधी, जोनल अधिकारी मोहित मिश्रा और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। आयुक्त ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य के दौरान लेफ्ट टर्न सर्विस रोड पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। यहां का काम पूरा होने से खजराना चौराहा से गणेश मंदिर मार्ग सुगम हो जाएगा।

पिछले काफी वक्त से ये काम जारी है। खास बात यह है कि पूरे सर्विस रोड का काम पूरा होने के बाद खजराना चौराहे पर जलजमाव की स्थिति नहीं बनेगी। साथ ही ट्रैफिक भी बेहतर हो जाएगा। निरीक्षण के दौरान पार्षद पुष्पेंद्र पाटीदार, अपर आयुक्त रोहित सिसोनिया, अभय राजनगांवकर, अधीक्षण यंत्री डीआर लोधी, जोनल अधिकारी मोहित मिश्रा, उपयंत्री केतन लोट व अन्य उपस्थित थे।

निर्माण कार्य से दो बड़े लाभ

1. जलजमाव की समस्या खत्म- रोड निर्माण के बाद खजराना चौराहा जलभराव से मुक्त होगा।
2. यातायात होगा सुगम- मंदिर जाने वाला मार्ग चौड़ा और व्यवस्थित हो जाएगा।

गंभीर टीबी का इलाज 9 महीने में, शुरू हुआ बीपीएएल इलाज

इंदौर। अब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस (एमडीआर-टीबी) से पीड़ित मरीजों को राहत की सांस मिलेगी। पहले जहां इलाज की अवधि 18 महीने तक होती थी, अब वही बीमारी सिर्फ 9 महीने में ठीक की जा सकेगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एमडीआर-टीबी मरीजों के लिए प्रभावी बीपीएएल उपचार पद्धति शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में इसके लिए आवश्यक दवाएं भेज दी गई हैं और कई जिलों में मरीजों को दवा वितरण भी शुरू कर दिया गया है। शनिवार को इंदौर के एमआरटीबी अस्पताल में एक मरीज को यह खुराक दी गई। बीपीएएल इलाज शासकीय अस्पतालों में पूरी तरह नि शुल्क रहेगा। जिले में फिलहाल सामान्य टीबी के 3200 मरीज हैं और एमडीआर-टीबी के 150 मरीज इलाजरत हैं।

क्या है बीपीएएल इलाज

बीपीएएल एक प्रभावशाली दवा संयोजन है, जिसमें बेडाक्विलाइन, प्रीटोमानिड और लाइनजोलिड नामक दवाएं दी जाती हैं। इनका असर तेज होता है और यह मरीजों को कम समय में ठीक कर देती हैं। पहले लंबी अवधि के इलाज से मरीज मानसिक तनाव में रहते थे, लेकिन अब सिर्फ 9 महीने में इलाज संभव है।

क्यों जरूरी है यह इलाज

एमडीआर-टीबी में सामान्य दवाएं असर नहीं करतीं क्योंकि मरीज के शरीर में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। ऐसे मरीजों का इलाज लंबा और चुनौतीपूर्ण होता है। भारत सरकार ने 2025 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य तय किया है, जिसे हासिल करने के लिए बीपीएएल जैसी आधुनिक चिकित्सा पद्धति को शुरू किया गया है। जिला क्षय अधिकारी डॉ शैलेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि बीपीएएल इलाज से गंभीर टीबी के मरीजों को तेजी से राहत मिलेगी। दवाएं निशुल्क दी जा रही हैं। इंदौर में एक मरीज को दवा देना शुरू कर दिया गया है।

कम्प्यूटर ऑपरेटर ने आत्महत्या की

इंदौर। छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के समाजवाद नगर में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतक अमित शेखर बोड़ाने पेशे से कम्प्यूटर ऑपरेटर था और एक समाचार पत्र में कार्यरत था। बताया जा रहा है कि वह पारिवारिक तनाव से गुजर रहा था और उसका अपनी पत्नी से तलाक का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। घटना की जानकारी तब सामने आई जब शनिवार सुबह परिवार वालों ने उसे कमरे में फांसी के फंदे पर लटका पाया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्ट्म के लिए भेज दिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें अमित ने अपने माता-पिता से माफी मांगी है और आत्महत्या का कारण व्यक्तिगत पारिवारिक तनाव बताया है। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद आत्महत्या की मुख्य वजह प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

संपादकीय

नए दलाई लामा पर विवाद

नए दलाई लामा की नियुक्ति को लेकर चीन और तिब्बती समुदाय के बीच विवाद गहराता जा रहा है। चीन का कहना है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन में उसकी भूमिका होनी चाहिए, जबकि दलाई लामा और तिब्बती समुदाय का कहना है कि यह फैसला पूरी तरह से तिब्बती बौद्ध परंपराओं और धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार होगा, जिसमें चीन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दलाई लामा ने कहा है कि उनके उत्तराधिकारी का चयन एक ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा, जिसमें तिब्बती आध्यात्मिक नेता, निर्वासित तिब्बती सरकार और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। तिब्बती समुदाय इससे सहमत है। जबकि चीन का कहना है कि दलाई लामाओं का पुनर्जन्म एक धार्मिक परंपरा है, लेकिन यह एक कानूनी और पारंपरिक प्रक्रिया भी है जिसमें चीन की भूमिका अनिवार्य है। चीन के अनुसार वह दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान के लिए 'गोल्डन अर्न प्रणाली' का उपयोग करेगा, जो एक पारंपरिक तरीका है जिसमें सोने के कलश में नामों को रखकर चयन किया जाता है। चीन के अनुसार दलाई लामा के पुनर्जन्म में धार्मिक और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना होगा, और इसमें चीन की केंद्रीय सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस बीच भारत ने भारत ने चीन के दावे का विरोध करते हुए कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन केवल दलाई लामा ही तय करेंगे। भारत के इस रूख पर भारत में चीनी राजदूत शू फेई होंगे ने गहरी नाराजी जताई है। दरअसल वर्तमान दलाई लामा 90 साल के हो चुके हैं, इसलिए उनके उत्तराधिकारी की खोज तेज हो गई है। लेकिन नए दलाई लामा की नियुक्ति केवल उत्तराधिकारी नामजदगी भर नहीं बल्कि यह तिब्बत की पहचान और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक चुनौती भी है। यह मुद्दा वैश्विक राजनीति में भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उधर दलाई लामा चीन को सीधी चुनौती देते हुए कहा है कि उनके नाम से संचालित सदियों पुरानी आध्यात्मिक संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहेगी तथा उनके उत्तराधिकारी की पहचान करने का अधिकार केवल उनके करीबी लोगों को होगा, न कि बीजिंग को। गौरतलब है कि चीन ने 1951 में तिब्बत पर कब्ज़ा कर लिया था और तब से इस क्षेत्र पर उसका कड़ा नियंत्रण है। उसने कहा है कि अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ़ बीजिंग के पास है और उसने कानून में सभी वरिष्ठ तिब्बती धार्मिक नेताओं के लिए राज्य की सहमति सुनिश्चित की है। उसका कहना है कि स्वर्ण कलश - किंग राजवंश की एक रस्म जिसमें औपचारिक बर्तन से लॉटरी द्वारा नाम निकाले जाते हैं - पुनर्जन्म वाले लामाओं को पहचानने का एकमात्र वैध तरीका है। कम्युनिस्ट पार्टी को अंतिम चयन को मंजूरी देनी चाहिए। बीजिंग ने 1995 में तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े आध्यात्मिक अधिकारी, 10वें पंचेन लामा की मृत्यु के बाद, दलाई लामा ने एक छह वर्षीय लड़के को अपना पुनर्जन्म माना। लड़का और उसका परिवार कुछ दिनों बाद चीनी हिरासत में गायब हो गया और तब से उसे नहीं देखा गया। चीन ने अपना खुद का उम्मीदवार स्थापित किया, जिसे तिब्बतियों ने व्यापक रूप से अस्वीकार कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, बीजिंग समर्थित पंचेन लामा ने पिछले महीने ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ ली। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दलाई लामा, अवलोकितेश्वर का सांसारिक रूप हैं, जिन्हें करुणा के बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है। वो एक आध्यात्मिक प्राणी हैं, जो दूसरों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए दुनिया में रहते हैं। बहरहाल इस विवाद को सर्वसम्मति से ही सुलझाना चाहिए।

नजरिया

अनिल ठाकुर

लेखक स्तंभकार हैं।

युद्ध, बुद्ध, समाजवाद, सेक्युलरिज्म की छाया में बिहार चुनाव

ऑपरेशन सिंदूर, ईरान-इजराइल युद्ध संबंधित विवाद अभी ठंडे भी नहीं हुए थे कि आरएसएस के सर कार्यवाहक होसबाले के सन् 1975 में संविधान में संशोधन कर समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ने को लेकर चर्चा करने के सुझाव से नया तूफान आ गया। कांग्रेस ने इसे लकपने में देरी नहीं की, राहुल गांधी को एक बार फिर संघ के साथ बीजेपी को कठघरे में खड़ा करने का सुनहरा मौका मिल गया। संघ सर कार्यवाहक होसबाले का यह बयान अनुचित नहीं मगर यह कहा जाए कि इसकी टाइमिंग भी अनुपयुक्त है, तो गलत नहीं होगा। संघ बीजेपी की मातृ संस्था है, यदि बीजेपी को नुकसान होता है तो संघ की विचारधारा को चोट पहुंचेगी।

भारत बुद्ध का देश है। हम हमेशा शांति समर्थक एवं युद्ध विरोधी रहे है। हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। हमेशा युद्ध थोपे जाने के बावजूद हम सहयोग और शांति के पक्षधर बने हुए है। प्रधानमंत्री मोदी कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों से बुद्ध के संदेश को दोहरा चुके है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति इतनी मजबूत हो गई है कि युद्ध हमारा अपना हो या किन्हीं अन्य देशों के बीच किसी ना किसी तरह हमारी अंतरराष्ट्रीय एवं आंतरिक राजनीति को प्रभावित करता है। धीरे धीरे दुनिया पुन: दो खेमों में विभाजन की तरफ जा रही है। ऐसे में भारत को तटस्थ बने रहने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध कही भी हो आंतरिक राजनीति के दो बड़े खेमों में बंट जाने से हमारे चुनाव नतीजों भी प्रभावित होते है। स्थिति यह हो गई है कि लगता है चुनाव नहीं दलों के बीच युद्ध हो रहा है। इन परिस्थियों में बिहार चुनाव नतीजे कितने प्रभावित होगे, यह कौतूहल बना हुआ है।

इसमें कोई दो मत नहीं कि पहलगाम में आतंकी हमलों में धर्म पूछकर की गई हत्याओं एवं ईरान इजराइल के युद्ध से उपजी परिस्थितियों ने हमारी अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के साथ आंतरिक राजनीति को भी बहुत हद तक प्रभावित किया है। ऑपरेशन सिंदूर को अचानक रोक देने एवं ईरान इजरायल के बीच चल रहे युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा में तत्काल युद्धविराम की मांग वाले प्रस्ताव में इजराइल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग में अनुपस्थित रहने को लेकर सरकार एवं विपक्ष में घमासान जारी है। पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध उचित कार्यवाही को लेकर सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के बीच जो सहमति बनी थी, वह दो दिन में ही तार तार हो गई थी। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि स्थगन, ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत सैन्य कार्यवाही, विदेश मंत्री के बयान, युद्ध विराम में अमरीकी राष्ट्रपति की भूमिका आदि के बारे में इतनी चर्चा हो चुकी है कि उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सारे मुद्दे बन गए है। कांग्रेस एवं अन्य विपक्ष का मसला सिर्फ यह है कि बीजेपी इसका लाभ बिहार चुनावों में ना ले पाए। इसलिए वह कोई ना कोई बहाना ढूंढकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। विपक्ष का व्यवहार कुछ सवाल जायज होने पर भी टाइमिंग के संदर्भ में अनुचित ही कहा जाएगा। कांग्रेस का हमारे कितने लड़ाकू विमान पाक ने मार गिराए वाले सवाल से उसकी मंशा के अतिरिक्त देश के प्रति निष्ठा पर भी शंका जाहिर करती है। भारत अभी तक पाकिस्तान से दो बार पारंपरिक युद्ध लड़ चुका है। अभी तक सरकार या सेना की और से अधिकृत या अनौपचारिक रूप से कभी नहीं बताया गया कि इन युद्धों में हमें कितने टैंक या लड़ाकू विमानो का नुकसान हुआ था, ना ऐसी कोई परंपरा है। तो फिर इस समय यह सवाल सेना का मनोबल गिराने का प्रयास नहीं तो क्या कहा जाए। जुलाई में संसद का अधिवेशन बुलाया जा चुका है, जहां सरकार इन सवालों से बच नहीं सकती, उसे जवाब तो देना ही है।

इसी तरह संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल की निंदा प्रस्ताव में अनुपस्थिति को लेकर भी विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि ईरान से हमारे सदियों पुराने संबंध है, अत: भारत ने ईरान का खुला समर्थन नहीं कर बहुत बड़ी गलती की है। जबकि सरकार का स्पष्ट मत है कि मतदान में अनुपस्थित रहकर हमने दोनों मित्र देशों के प्रति समान रवैया अपनाया एवं शांतिपूर्ण ढंग से समस्या के निदान का आग्रह किया था। यदि ईरान हमारा पुराना मित्र है तो इजराइल ने भी हर युद्ध के समय सैन्य सहायता एवं समर्थन किया है।

ऑपरेशन सिंदूर, ईरान-इजराइल युद्ध संबंधित विवाद अभी ठंडे भी नहीं हुए थे कि आरएसएस के सर कार्यवाहक होसबाले के सन 1975 में संविधान में संशोधन कर समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ने को लेकर चर्चा करने के सुझाव से नया तूफान आ गया। कांग्रेस ने इसे लकपने में देरी नहीं की, राहुल गांधी को एक बार फिर संघ के साथ बीजेपी को कठघरे में खड़ा करने का सुनहरा मौका मिल गया। संघ सर कार्यवाहक होसबाले का यह बयान अनुचित नहीं मगर यह कहा जाए कि इसकी टाइमिंग भी अनुपयुक्त है, तो गलत नहीं होगा। संघ बीजेपी की मातृ संस्था है, यदि बीजेपी को नुकसान होता है तो संघ की विचारधारा को चोट पहुंचेगी।

बिहार चुनाव में इन मुद्दों का कितना असर होगा यह विश्लेषण करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि बिहार एवं उत्तरप्रदेश की राजनीति आज भी जातिवाद केंद्रित है। जबकि उत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे मप्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं गुजरात में नेतृत्व क्षमता एवं मुद्दे प्रमुख कारक होते है। यह भी देखने में आया है कि राज्य चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दे ज्यादा असरकारक एवं निर्णायक होते है। बिहार चुनाव में यादवों एवं बिहार के कुछ जिलों में मुस्लिमों की घनी आबादी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिहार में यादवों के एकछत्र नेता लालू यादव है इसमें किसी को कोई शंका नहीं है। कुछ मजबूरियों के चलते उन्होंने पार्टी की कमान अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव को सौंप दी थी। यह कहने में भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी एक सशक्त नेता के रूप में उभरे है। कमजोर से कमजोर मुद्दे पर भी नीतीश सरकार को घेरने में वे कोई चूक नहीं करते। बिहार एवं उत्तरप्रदेश में यादव मुस्लिम समीकरण चुनाव में असर कारक होता है। इसीलिए बिहार में कांग्रेस राजद के साथ गठबंधन को आतुर थी, लेकिन कन्हैया कुमार एवं तेजस्वी के बीच वर्चस्व की लड़ाई बहुत बढ़ी बाधा थी।

राहुल ने बिहार के दो तीन दौरे कर किसी तरह अभी तो इस समस्या को सुलझाकर राजद से समझौता कर लिया है। लेकिन देखना होगा कि सीट बंटवारे में कांग्रेस कितनी सीट हांसिल कर पाती है। पिछले चुनाव में अच्छी संख्या में सीट मिलने के बावजूद बहुत कम सीटे जीत पाई थी। तेजस्वी ने पिछले कुछ समय में अपनी लोकप्रियता में बढ़ोतरी की है, इसलिए वे किसी दबाव में आयेंगे, ऐसा नहीं लगता। तेजप्रताप यादव प्रसंग से यादव परिवार में कलह से पार्टी को कोई विशेष नुकसान की संभावना नहीं दिखती। कांग्रेस के कन्हैया कुमार अपनी तर्क एवं कुशल वक्तृत्व शैली के बावजूद मतदाताओं को प्रभावित करने में दो चुनाव हारकर नाकाम ही रहे है। स्वर्ण जाति के होने से पिछड़े वर्ग को वे शायद ही आकर्षित कर पाए।

एनडीए गठबंधन के लिए भी राह आसान नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के स्वास्थ्य एवं मानसिक स्थिति को लेकर कई बातें हवा में होने के बावजूद पार्टी में उनकी पकड़ एवं वोट बैंक मजबूत है। चिराग पासवान के बिहार की राजनीति में आने की चर्चा से उनकी मुश्किलें बढ़ी है। चिराग की वजह से ही पिछले चुनाव में उन्हें अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा था। यह तो बीजेपी ने वक्त की नजाकत एवं नीतीश बाबू के पिछले इतिहास को देखते हुए उन्हें अपने खेमे में बनाए रखा वरना बीजेपी के मुख्यमंत्री लिए पांच वर्ष सरकार चलाना मुश्किल होता। चिराग पासवान की पार्टी कितनी सीटें निकाल पाएगी बिहार में उनका भविष्य उसी अनुसार तय होगा। चिराग के निर्णय से बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ना स्वाभाविक है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी अभी तक पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ नहीं बना पाए है। बीजेपी किस तरह शक्ति संतुलन साधती है, बहुत कुछ इस पर निर्भर होगा। अमित शाह एवं प्रधानमंत्री हमेशा की तरह बिहार चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की शुरुआत कर चुके है। तेजस्वी एवं पीके जैसे दो सशक्त विरोधियों के होते एनडीए कितने संगठित तरीके से चुनाव लड़ता है सारा दारोमदार उसी पर है। कांग्रेस की स्थिति ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। लेकिन राहुल गांधी का संविधान बचाओ का नारा पार्टी एवं गठबंधन को फायदा पहुंचा सकता है। इसके विपरीत मोदी का राष्ट्रवाद एवं जातीय जनगणना का निर्णय कितना कारगर होगा यह नतीजों से पता चलेगा। नीतीश सरकार के लिए एंटी इनकंबेंसी इस बार कुछ असर दिखाएगी यह संभव है।

एजेंसियों के सर्वे में अभी तो तेजस्वी आगे बने हुए है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व अंतिम समय तक अपनी रणनीति एवं मेहनत में कोई कसर नहीं रखता। संघ की भूमिका का बीजेपी में महत्वपूर्ण रोल होता है, बीजेपी नेतृत्व किस तरह संघ से सामंजस्य बना कर लक्ष्य हासिल करता है, यह अहम सवाल है। अभी बिहार चुनाव में करीब तीन माह बाकी है, तेजी से बदलती घटनाओं की श्रृंखला में कब कौन सा नया नरेटिव जन्म ले ले कुछ कह नहीं सकते।

नीति

प्रमोद भार्गव

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

अमेरिकी कृषि उत्पाद बेचने से बचे भारत

भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई से पहले व्यापार समझौता होना हैं। यदि भारत अमेरिका की शर्तें नहीं माना है तो 9 जुलाई से टैरिफ यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगाया जाने वाला कर 10 से बढ़ाकर 26 प्रतिशत हो जाएगा। भारत चाहता है कि जल्द अंतरिम व्यापार समझौता हो जाए। लेकिन अमेरिका अपने हितों को प्राथमिकता देते हुए चाहता है कि भारत में उसे कृषि और डेयरी उत्पाद बचने की अनुमति दी जाए। चीन ने अमेरिकी उत्पात खरीदने से मना कर दिया है। भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दबाव के बावजूद अमेरिका के लिए कृषि उत्पाद का बाजार खोलने के पक्ष में नहीं है। दरअसल भारत की 70 करोड़ से भी अधिक आबादी कृषि, दूध और मछली व अन्य समुद्री उत्पादन पर आश्रित है। इन उत्पादों से जुड़े लोग आत्मनिर्भर रहते हुए अपनी आजीविका चलाते हैं। हालांकि भारत सरकार इनकी आर्थिक स्थिति को ओर मजबूत बनाए रखने की दृष्टि से मुफ्त अनाज, खाद्य सब्सिडी और किसानों को छह हजार रुपए प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में देती है।

भारत की 70 प्रतिशत अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि और उससे जुड़े उत्पाद हैं। अब अमेरिका इस परिप्रेक्ष्य में भारत पर व्यापक दबाव बनाकर द्विपक्षीय बातचीत करने का दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तो खुले ही उत्पादों पर शुल्क भी कम करे। यदि भारत कोई समझौता करता है तो ब्रिटेन और यूरोपीय संघ भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के लिए दबाव बनाएंगे। यूरोपीय संघ चीज व अन्य दुग्ध उत्पादों पर शुल्क कटौती की इच्छा जता चुका है। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर ने भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से बातचीत में इन मुद्दों को द्विपक्षीय वार्ता में शामिल करने की बात कही है। किंतु भारत के लिए कृषि में बाहरी दखल एक संवेदनशील मसला है, क्योंकि हमारे किसान विदेशी पूंजीपतियों से प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में नहीं हैं।

भारत में कृषि केवल आर्थिक गतिविधि नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक सांस्कृतिक तरीका भी है। इसीलिए भारत के जितने भी पर्व हैं, उनका पंचांग कृषि पद्धति पर ही आधारित है। जबकि अमेरिका व यूरोपीय देश कृषि को मुनाफे का उद्योग मानते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका का कृषि निर्यात 176 अरब डॉलर था, जो उसके कुल व्यापारिक निर्यात का लगभग 10 प्रतिशत हैं। बड़े पैमाने पर मशीनीकृत खेती और भारी सरकारी सब्सिडी के साथ अमेरिका और अन्य विकसित देश भारत को अपने निर्यात का विस्तार करने के लिए आकर्षक बाजार के रूप में देखते हैं। जबकि भारत अपने कृषि क्षेत्र को मध्यम से उच्च शुल्क की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा संरक्षित किए हुए है ताकि अपने किसानों को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके। कृषि क्षेत्र को मुक्त बाजार बनाने का मतलब है कि आयात प्रतिबंधों और शुल्कों को कम करना। कृषि को बाहरी सब्सिडी वाले विदेशी आयातों के लिए खोलने का अर्थ होगा, सस्ते खाद्य उत्पादों का भारत में आना, यह खुलापन भारतीय किसानों की आय और आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित करेगी।

ऐसा ही दबाव भारत पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने जेनेवा में 2022 में हुई बैठक में बनाया था। यहां तक कि अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों ने भारतीय किसानों को दी जाने वाली कृषि अनुवृत्ति (सब्सिडी) का जबरदस्त विरोध किया था। ये देश चाहते हैं कि किसानों को जो सालाना छह हजार रुपए की आर्थिक मदद और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की सुविधा दी जा रही है, भारत उसे तत्काल बंद करे। यही नहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देशभर के 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है उस पर भी आपत्ति जताई थी। देश की करीब 67 फीसदी आबादी को मुफ्त अनाज मिलता है। इस कल्याणकारी योजना पर 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपए का खर्च सब्सिडी के रूप में प्रति वर्ष होता है। परंतु भारत ने अपने किसान और गरीब आबादी के हितों से समझौता करने से साफ इंकार कर दिया था। इसे डब्ल्यूटीओ के तय नियमों का खुला उल्लंघन करार दिया गया था। क्योंकि नियमानुसार अनाजों के उत्पादन मूल्य पर 10 प्रतिशत से ज्यादा सब्सिडी नहीं दी जा सकती है। जबकि भारत इससे कई गुना ज्यादा सब्सिडी देता है। दरअसल इन देशों का मानना है कि सब्सिडी की वजह से ही भारतीय किसान चावल और गेहूं का भरपूर उत्पादन करने में सक्षम हुए हैं। इसी का परिणाम है कि भारत गेहूं व चावल के निर्यात में अग्रणी देश बन गया है। बांग्लादेश, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, फिलीपींस और नेपाल के अलावा 68 देश भारत से गेहूं आयात करते हैं। भारत दुनिया के कुल 150 देशों को चावल का निर्यात करता है। अमेरिका को भारत की यह समृद्धि फूटी आंख नहीं सुहा रही है।

किसी भी देश की प्रतिबद्धता विदेशी हितों से कहीं ज्यादा देश के किसान, गरीब व वंचित तबकों की खाद्य उत्पादन और सुरक्षा के प्रति ही होनी चाहिए। लिहाजा नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के समय से ही किसानों के हित में खड़े दिखाई दिए हैं। अतएव 2014 में इसी जेनेवा में डब्ल्यूटीओ के हुए सम्मेलन में नरेंद्र मोदी ने भागीदारी करते हुए 'समुचित व्यापार अनुबंध' (ट्रेड फैलिसिटेशन एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इस करार की सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी कि संगठन का कोई भी सदस्य देश,अपने देश में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों के मूल्य का 10 फीसदी से ज्यादा अनुदान खाद्य सुरक्षा पर नहीं दे सकता है। जबकि भारत खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश की 67 फीसदी आबादी खाद्य सुरक्षा के दायरे में है। इसके लिए बतौर सब्सिडी जिस धनराशि की जरूरत पड़ती है, वह सकल फसल उत्पाद मूल्य के 10 फीसदी से कहीं ज्यादा बैठती है। दरअसल सकल फसल उत्पाद मूल्य की 10 फीसदी सब्सिडी का निर्धारण 1986-88 की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आधार पर किया गया था। इन बीते साढ़े तीन दशक में मंहगाई ने कई गुना छलांग लगाई है। इसलिए इस सीमा का भी पुनर्निर्धारण जरूरी है। यही वह दौर रहा है, जब भूमण्डलीय आर्थिक उदारवाद की अवधारणा ने बहुत कम समय में ही यह प्रमाणित कर दिया कि वह उपभोक्तावाद को बढ़ावा देकर अधिकतम मुनाफा बटोरने का उपाय भर है।

टीएफए की सब्सिडी संबंधी शर्त, औद्योगिक देश और उनकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के इसी मुनाफे में और इजाफा करने की दृष्टि से लगाई गई है। जिससे लाचार आदमी के आजीविका के संसाधनों को दरकिनार कर उपभोगवादी वस्तुएं खपाई जा सकें। नवउदारवाद की ऐसी ही इकतरफा व विरोधाभासी नीतियों का नतीजा है कि अमीर और गरीब के बीच खाई लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल देशी व विदेशी उद्योगपति पूंजी का निवेश दो ही क्षेत्रों में करते हैं, एक उपभोक्तावादी उपकरणों के निर्माण और वितरण में, दूसरे प्राकृतिक संपदा के दोहन में। यही दो क्षेत्र धन उत्सर्जन के अहम स्रोत हैं। उदारवादी अर्थव्यवस्था का मूल है कि भूखी आबादी को भोजन के उपाय करने की बजाय विकासशील देश पूंजी का केंद्रीकरण एक ऐसी निश्चित आबादी पर करें,जिससे उसकी खरीद क्षमता में निरंतर इजाफा होता रहे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता

प्रियंका सौरभ

लेखक शोधार्थी हैं।

नवाचार की उड़ान या बौद्धिक चोरी

इक्कीसवीं सदी की सबसे बड़ी तकनीकी छलांगों में से एक है जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता – यानी ऐसा कंप्यूटर मस्तिष्क जो कहानी से लेकर समाचार रिपोर्ट, चित्र से लेकर कविता, और अदालत के निर्णय से लेकर संवाद तक खुद रच सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इस मशीनी रचनात्मकता की नींव क्या किसी और की मेहनत पर टिकी है? क्या यह नई तकनीक रचनाकारों, लेखकों, पत्रकारों, चित्रकारों और संगीतकारों की बनाई सामग्रियों को चुपचाप अपने ज्ञान का हिस्सा बना रही है – बिना उनकी अनुमति, बिना कोई श्रेय दिए? हाल ही में अमेरिका की दो अदालतों में ऐसे ही मामलों पर निर्णय हुआ। इन फैसलों ने फिलहाल तकनीकी कंपनियों को राहत दी है, पर यह विषय अभी भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। इन फैसलों ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी है – और भारत भी इससे अछूता नहीं है।

जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले मॉडल – जैसे कि ओपनएआई का चैटजीपीटी या मेटा का लामा – करोड़ों पुस्तकों, वेबसाइटों, गीतों, समाचारों और चित्रों का अध्ययन करके प्रशिक्षित किए जाते हैं। इनका प्रशिक्षण इस तरह होता है जैसे कोई छात्र पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन यह छात्र उस पुस्तक को पढ़ने से पहले लेखक से न अनुमति लेता है, न ही लेखक को श्रेय या पारिश्रमिक देता है। यही से विवाद आरंभ होता है।

2024 में अमेरिका में पहला मामला आया जिसमें कुछ उपन्यासकारों ने कंपनी 'एंथ्रॉपिक' पर आरोप लगाया कि उसने उनकी पुस्तकों का उपयोग अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए किया। लेखकों का कहना था कि यह उनकी बौद्धिक संपदा का उल्लंघन है। परंतु अदालत ने निर्णय दिया कि यह मॉडल जो नई सामग्री उत्पन्न कर रहा है, वह मूल रचना से अलग, नया और परिवर्तित है। इसलिए यह 'उचित प्रयोग' की श्रेणी में आता है और कंपनी को अपराधी नहीं माना जा सकता।

दूसरे मामले में कंपनी मेटा पर साहित्य और पत्रकारिता सामग्री को बिना अनुमति इस्तेमाल करने का आरोप था। अदालत ने माना कि कंपनी ने सचमुच संरक्षित रचनाएं पढ़ी थीं, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ नया सीखना और बनाना था, इसलिए इसे भी 'परिवर्तनकारी उपयोग' मानते हुए मेटा को दोषमुक्त कर दिया गया।इन दोनों फैसलों से एक संदेश यह गया कि न्यायालय फिलहाल तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन लेखक समुदाय और बौद्धिक श्रमिकों के मन में यह सवाल घर करता जा रहा है कि यदि यह 'उचित प्रयोग' है, तो उनकी मेहनत, मौलिकता और अधिकारों का क्या? अब दृष्टि भारत की ओर मोड़ते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने वर्ष 2024 में ओपन एआई पर आरोप लगाया कि उसके संवाद आधारित मॉडल (जैसे चैटजीपीटी) उनकी समाचारों की भाषा, शैली और विषय-वस्तु की हूबहू नकल कर रहा है। इसके अलावा प्रकाशक संघों ने भी आरोप लगाए कि भारत में कॉपीराइट पंजीकरण की अनदेखी कर इन एआई कंपनियों ने भारतीय सामग्री का व्यावसायिक दोहन किया। ओपनएआई का पक्ष यह था कि वह भारत में न तो अपने सर्वर चलाता है, न ही उसका कोई स्थायी कार्यालय है। उसका तर्क था कि उसकी तकनीक कुछ नया, परिवर्तित और जनहित में उपयोगी सामग्री तैयार करती है – और यह बौद्धिक चोरी नहीं कहलाती।यह मामला अब दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, और इसकी सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में निर्धारित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत में अब यह बहस न्यायिक गलियारों में पहुंच चुकी है।

प्रश्न यह है कि क्या भारत का मौजूदा बौद्धिक संपदा कानून इस नई तकनीकी चुनौती के लिए तैयार है? 1957 में बनाए गए कॉपीराइट अधिनियम में 'उचित प्रयोग' की धारणा है, पर उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे मामलों की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। ना ही भारत में ऐसा तंत्र है जो यह जांच सके कि कोई एआई मॉडल प्रशिक्षण के लिए किन सामग्रियों का उपयोग कर रहा है और वे सामग्री कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं या नहीं।

आज लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार, फोटोग्राफर और पत्रकार यह महसूस कर रहे हैं कि उनका सृजन कार्य मशीनों के पेट में डाला जा रहा है, और बदले में उन्हें न कोई श्रेय मिल रहा है, न ही पारिश्रमिक। यह न केवल कानूनी बल्कि नैतिक चिंता का विषय है। इस विषय पर बहस यह नहीं है कि तकनीक को रोका जाए। नवाचार और प्रौद्योगिकी की प्रगति आवश्यक है, लेकिन वह प्रगति ऐसी न हो जो मानवीय रचनात्मकता को निगल जाए। अगर कोई लेखक दस वर्षों की मेहनत से एक उपन्यास रचता है, और कोई मशीन दो सेकंड में उसकी शैली की नकल करके नया 'उत्पाद' बनाती है, तो यह न तो न्यायसंगत है, न ही सम्मानजनक। न्यायालयों की जिम्मेदारी अब केवल यह नहीं रह गई कि वे कंपनियों और व्यक्तियों के बीच विवाद सुलझाएं, बल्कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य का तकनीकी विकास समान रूप से सभी के हित में हो। केवल पूंजी और तकनीक के सहारे अगर किसी का बौद्धिक श्रम मुफ्त में हड़पा जा रहा है, तो वह लोकतांत्रिक और नैतिक मूल्यों का उल्लंघन है।

भारत को चाहिए कि वह अपने कॉपीराइट कानूनों की पुनर्रचना करे – विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग के अनुरूप। ऐसी व्यवस्था बने जिसमें रचनाकारों की रचनाओं को यदि तकनीक द्वारा उपयोग किया जा रहा है तो उन्हें उसका पारिश्रमिक मिले, उनके नाम का उल्लेख हो, और उनकी अनुमति अनिवार्य हो।

यह केवल न्याय की बात नहीं है, यह साहित्य, संस्कृति और रचनात्मकता की रक्षा की बात है। यदि हम अपने समय के रचनाकारों की अनदेखी करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ तकनीक तो पाएंगी – पर संवेदना नहीं, आत्मा नहीं।

मशीनों को दी उड़ान, पर कलम से छीना आसमान, बिना श्रेय के ज्ञान अगर, तो कैसा विज्ञान?

सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

गोविन्द सेन

लेखक व्यंग्यकार हैं।

शेर, बकरी और शास्त्र

शेर और बकरी में दोस्ती नहीं हो सकती । बकरी शेर की भक्त ही हो सकती है, दोस्त नहीं । यदि शेर अपने को बकरी का दोस्त बताता है तो समझो, वह नाटक कर रहा है । उसकी नज़र बकरी के मांस पर ही होती है । बकरी को शेर पर श्रद्धा रखनी होगी । दूसरा विकल्प नहीं है । यदि बकरी शेर को अपना दोस्त मानती है तो वह बहुत भोली है ।

धंधे में धर्म आड़े नहीं आता । धर्म का धंधा खूब चलता है । सदियों से चल रहा है । खूब चल रहा है । यह बिना पूँजी का धंधा है । धर्म में जो प्राणी अकटनीय है, वह धंधे में कटनीय है । धंधे में दया नहीं है । धर्म में दया ही दया है । हम तुम पर दया करेंगे । और दयापूर्वक काटेंगे भी । इसीलिए धर्म और धंधा दोनों साथ-साथ चलते रहते हैं । कहीं कोई टकराव नहीं होता है । धर्म शेर को बकरी का भक्षण करने की इजाज़त देता है । शेर शाकाहारी नहीं हो सकता । बकरियों को तो शाकाहारी ही रहना है । बकरी का धर्म है, खुद को शेर का आहार बनाना ।

यदि कोई बकरी किसी शेर के जमे जमाए धंधे को छीनने की कोशिश करती है तो धर्म चुप नहीं बैठता । अपनी टांग अड़ा देता है । हमारा धर्म एक है तो क्या हुआ, धंधा एक नहीं । तेरा धंधा तू कर, मेरा धंधा मैं करूँगा । सुन बकरी, मेरा धंधा मैं ही करूँगा । मेरा धंधा करने का तुझे अधिकार नहीं । शास्त्र में यही लिखा है । वह पुराना शास्त्र खोलकर दिखा देता है । देख मूरख, शास्त्र में लिखा है । शास्त्र ही शस्त्र है । शास्त्र ही अस्त्र है । शास्त्र सर्वोपरि है । गैलीलियो को पुरानी किताब खोलकर बता दी गई । सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है । पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगाती । तेरी थ्योरी तू तेरे पास रख, सूरज हमारी किताब के मुताबिक ही चक्कर लगाएगा । हमारा शास्त्र जो कहता है, वही सत्य है । गैलीलियो के पास तो केवल सत्य था । शास्त्र के सामने सत्य नहीं टिकता । शास्त्र सत्य को पग-पग पर परेशान करता है । गैलीलियो को पुराने जर्जर शास्त्र के सामने घुटने टेकने पड़े थे । सत्य को हर युग में शास्त्रों का हवाला देकर झूठा साबित किया जाता रहा है । अनेक बार चमत्कारी चरणों में सत्य को झुकना पड़ा है । लोग विज्ञान को चमत्कारी नहीं मानते, बाबा को चमत्कारी मानते हैं ।

कल का टपोरी चमत्कारी बाबा बनकर धंधा करने लगता है । वह भक्तों को दानी और त्यागी बनने के लिए जुटा रहता है । खुद डेढ़ लाख का चश्मा पहनता है । चाँदी का मुकुट धारण करता है । जंघा ठोककर भीख माँगता है–'दे दे, नहीं तो छीन लेंगे ।' रंगीन झोली लेकर चार्टर प्लेन में देश विदेश की यात्रा करता है । वह लोगों के भूत भगाता है, इसके लिए उसे महाभूत बनना पड़ता है। वह लोगों के भविष्य बता-बता कर अपना भविष्य उज्ज्वल करने में जुटा हुआ है बकरियो ।

वह जो कह दे वही सत्य होता है । पत्थर की लकीर। सामंत उसके चरणों में लोटते हैं । विज्ञान को भी चमत्कारी बाबा के चरणों में अपना शीश झुकाना पड़ता है । चमत्कार करने का अधिकार अब केवल बाबा को है, विज्ञान को नहीं । इसीलिए शेरों का धंधा शेरों को करने दो । बकरियों को अपनी औकात में रहना चाहिए । बकरियाँ शेर का खाद्य हैं । चुपचाप खुद को शेर के हवाले करने में ही बकरियों की भलाई है ।

38 प्रतिशत आंगनवाड़ियों में बच्चे गंभीर कुपोषण के शिकार

सरोकार

डॉ. चन्दर सोनाने

लेखक मप्र जनसंपर्क विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं।

मध्यप्रदेश में कुल 97,000 से अधिक आंगनवाड़ियां हैं। इन आंगनवाड़ियों में से 38 प्रतिशत आंगनवाड़ियों में बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। मजेदार बात यह है कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में कुपोषण से लड़ने के लिए 4,895 करोड़ का बजट रखा गया है। इसके बावजूद प्रदेश में गंभीर कुपोषण से शिकार बच्चों की संख्या देखते हुए यह स्पष्ट दिखता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में कुप्रबंध है।

महिला एवं बाल विकास विभाग के पोषण ट्रैकर एप के विश्लेषण में उक्त चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश में कुपोषण राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। गंभीर और मध्यम कुपोषण के मामले जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर अप्रैल 2025 में 5.40 प्रतिशत थे, वहीं मध्यप्रदेश में यह 7.79 प्रतिशत था। प्रदेश में अप्रैल 2024 में यह 2025 की तुलना में कम 6.87 प्रतिशत था। 2024 की तुलना में 2025 में यह प्रतिशत घटने की बजाय बढ़ गया। 6 साल से कम उम्र के 27 प्रतिशत लड़कों में दुबलापन पाया गया है। इसी आयु वर्ग में 32 प्रतिशत लड़कियों का वजन उम्र के मुताबिक कम पाया गया। मध्यप्रदेश में कुपोषण से लड़ने के लिए हजारों करोड़ों रूपए का प्रावधान बजट में रखने के बावजूद अभी भी अधिकतर जिलों में पोषण की हालत सुधरी नहीं है। मई माह में प्रदेश के 55 जिलों में से 45 जिलों के बच्चे कम वजन के मामले में रेड जोन में हैं। अर्थात 20 प्रतिशत से अधिक बच्चों का वजन उम्र के अनुसार कम पाया गया है। यही नहीं 22 जिलों में बच्चों में ठिगनापन भी देखा गया है। अर्थात बच्चों की ऊँचाई उसकी उम्र के मुताबिक कम पाई गई है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में 6 साल तक की उम्र के बच्चे गंभीर और मध्यम कुपोषण से जुझ रहे हैं। बड़े जिलों में भी गंभीर कुपोषण वाले बच्चे पाये गए हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण वाले देखे गए। इन्दौर जिले में 45 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषण वाले हैं। उज्जैन में 46 प्रतिशत बच्चे गंभीर कुपोषित पाए गए हैं। ग्वालियर और चंबल में लगभग 35 प्रतिशत गंभीर कुपोषण वाले बच्चे रजिस्टर्ड हैं।

प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया ने विधानसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया था कि मध्य प्रदेश की आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 62.88 लाख बच्चों में से 5.41 लाख कम वजन के हैं। इनमें सबसे ज्यादा धार जिले में है। धार जिले में सबसे ज्यादा 35,950 कम वजन वाले बच्चे पंजीकृत हैं। इसके बाद खरगोन में 24,596 और बड़वानी में 21,940 बच्चे पंजीकृत हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल जिले में 12,199 कम वजन वाले बच्चे हैं। इंदौर में 11,437 बच्चे कम वजन के हैं। उक्त आंकड़ों के अनुसार, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में ऐसे बच्चों की संख्या 12,039 है, जबकि निवाड़ी में सबसे कम 1,438 बच्चे हैं।

प्रदेश में 97 हजार से आंगनवाड़ियाँ हैं। इन आंगनवाड़ियों में गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और 6 साल तक के बच्चे दर्ज किए जाते हैं। इन बच्चों को पौष्टिक आहार प्रतिदिन मिलता रहे इसके लिए महिला बाल विकास के द्वारा इन आंगनवाड़ियों में पोषण आहार दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ईकाई आंगनवाड़ी होती है। आंगनवाड़ियों की देखरेख के लिए पर एक पर्यवेक्षक की तैनाती की जाती है। एक परियोजना में करीब एक सौ आंगनवाड़ियां होती

है। परियोजना अधिकारी इस परियोजना का मुख्य कर्ताधर्ता रहता है। जिले की समस्त परियोजनाओं पर एक जिला स्तर का अधिकारी होता है। आंगनवाड़ियों में कुपोषित बच्चे पाए जाने पर उन्हें विशेष पोषण आहार दिया जाता है। इससे बच्चे कुपोषण से बाहर निकलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। कुछ वर्ष पहले महिला बाल विकास विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों को गोद में लेने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना में कोई भी सामाजिक, स्वयंसेवी संस्था आंगनवाड़ियों को गोद ले सकती है। एक आंगनवाड़ी के गंभीर कुपोषित बच्चों को कोई व्यक्ति भी गोद ले सकता है। एक व्यक्ति एक से अधिक कुपोषित बच्चों को गोद ले सकता है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए गोद लेने वाले व्यक्ति और संस्थाओं को एक बच्चे के लिए एक माह की खाद्य सामग्री की सूची और मात्रा दी जाती थी। वह व्यक्ति और संस्था प्रतिमाह खाद्य सामग्री आंगनवाड़ियों को देता था। इससे बच्चे तेजी से कुपोषण से बाहर निकलने लगते थे।

अभी भी कुपोषित बच्चों को गोद लेने की आंगनवाड़ियों में यह व्यवस्था है। यह योजना अब केवल कागज पर है। किन्तु उसमें कोई भी रूचि नहीं लेता है। न तो आंगनवाड़ियों कार्यकर्ता इसमें रूचि लेती है, न पर्यवेक्षक और न ही परियोजना अधिकारी इसमें रूचि लेता है। इसी कारण से यह अत्यन्त उपयोगी योजना सुप्त अवस्था में चली गई है। इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आंगनवाड़ियों में गंभीर कुपोषित पाए गए बच्चों की हर स्तर पर सतत समीक्षा करने की भी सख्त आवश्यकता है। समाज के सक्रिय सहयोग से और विभाग के हर स्तर के अधिकारियों कर्मचारियों के सहयोग से ही बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला जा सकता है।

किसी भी सरकार का दायित्व होता है कि वे अपने राज्य में कुपोषण को समाप्त करें। विशेषकर बच्चों में गंभीर कुपोषण पाया जाना दुखद होता है। इससे वे असमय ही काल के ग्रास बन जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण को समाप्त करने की दिशा में प्राथमिकता के आधार पर कार्य करें।

शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग की अति से बचें

शिक्षा प्रणाली

भूपेन्द्र भारतीय

लेखक अधिवक्ता हैं।

एक बार फिर देखने में आ रहा है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सिर्फ़ निरंतर प्रयोगों से ही गुजर रही है। प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। अधिकांश बंद होने के कगार पर है। इसके लिए कोई जिम्मेदारी तय नहीं हो पा रही है। सरकार कभी अभिभावकों को तो कभी निजीकरण को दोष दे रही है। आखिर प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे निजी स्कूलों में ही क्यों जाने को मजबूर हैं ? सरकार इस समस्या पर गंभीर नहीं है। ऊपर से जिन प्राथमिक विद्यालयों में बच्चें कम उन्हें या तो बंद करने पर विचार हो रहा है या फिर उन्हें अन्य स्कूलों में विलय करके खत्म करना। जो कि प्राथमिक शिक्षा के लिए घातक होगा। साथ ही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़। निरंतर शिक्षा क्षेत्र में प्रयोग हो रहे हैं। कभी विद्यालयों-विश्वविद्यालयों के नाम की राजनीति तो कभी पाठ्यक्रम बदलते रहना, भाषा की लड़ाई ने पूर्णतः राजनीतिक अखाड़े का रूप ले लिया है। नेता जमकर एक दूसरे पर भारतीय भाषाओं में आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। देश के बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों से युवा पढ़कर विदेश में नौकरी करने की इच्छा अब भी ज्यादा रखते हैं! रिसर्च के नाम पर ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को नहीं आ रहे हैं। उच्च शिक्षा में भी हर साल प्रयोग की अति बढ़ती जा रही है। पर परिणाम में फिसड्डी हो रहे हैं। वहीं शिक्षा में अधिकांश बदलाव का धरातल पर सकारात्मक पक्ष नहीं दिख रहा है। बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए अभिभावक बच्चों को निजी स्कूलों में भेजने के लिए मजबूर हैं। निजी शिक्षा क्षेत्र अभिभावकों की अधिकांश कमाई धड़ल्ले से लूट रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में निजी संस्थानों का

मकडज़ाल देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। शिक्षा के मामले में अभिभावकों का विश्वास सरकारें स्वतंत्रता के 75 वर्षों में भी नहीं जीत पा रही है। शिक्षा जैसा पवित्र कार्य व्यापार बन गया है।

चूंकि भारत के संविधान में शिक्षा राज्य का विषय है। हर राज्य में शिक्षा की अपनी व्यवस्था, पाठ्यक्रम व अलग अलग भाषा है। ऐसे में पूरे राष्ट्र में कोई एक समान शिक्षा व्यवस्था नहीं है। दक्षिण राज्यों में भाषा के नाम पर आये दिन टकराव होता है। वही उत्तर के राज्यों में शिक्षा विभागों में घोर लापरवाही, कामचोरी, भ्रष्टाचार व नकल के मामले देखने में आते हैं। भारत की स्कूली शिक्षा प्रणाली स्वतंत्रता के बाद से ही मैकाले नीति व मानसिकता के कारण संघर्ष कर रही है, वर्तमान में ASER 2024 रिपोर्ट व अन्य सूत्रों के अनुसार, सरकारी स्कूलों में केवल 23.4 प्रतिशत कक्षा 3 के छात्र ही कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ने में सक्षम हैं। सार्वजनिक शिक्षा पर व्यय GDP का मात्र 4.6 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 द्वारा निर्धारित 6 प्रतिशत लक्ष्य से कम है। कई राज्यों में शिक्षकों की भारी कमी है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक रिक्तियाँ हैं, जिसके कारण छात्र-शिक्षक अनुपात बहुत अधिक (47:1 तक) है और शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में एक लाख से अधिक रिक्तियाँ हैं तथा शिक्षकों का एक उल्लेखनीय प्रतिशत अभी भी अयोग्य है। अकेले मध्यप्रदेश के सरकारी विद्यालयों में करीब 18 हजार सरकारी स्कूल एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रहे हैं।

वहीं मध्यप्रदेश के करीब साढ़े तीन हजार ऐसे स्कूल हैं, जहां एक भी बच्चा नहीं है, लेकिन शिक्षक तैनात हैं। वहीं प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भरमार है और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल खाली हैं। अकेले मध्यप्रदेश में करीब छह हजार अतिशेष शिक्षक है। देश के अन्य राज्यों में स्तिथियों का आकलन लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की प्राथमिक शिक्षा के मामले में बात करे तो यहां हाल ही में करीब पांच हजार प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वही इससे पहले राजस्थान और अन्य राज्यों की सरकारें भी हजारों स्कूलों को विलय के नाम पर बंद कर चुकी हैं। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला पीछले दिनों पूरे देश में चर्चित रहा व इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों की शिक्षा की चिंता करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ कठोर टिप्पणी की !

वास्तव में, भारत की शिक्षा नीति दशकों से एक प्रयोगशाला में तब्दील हो गई है, जहाँ हर नई समिति, शिक्षाविद् और नीति निर्माता अपनी समझ से कुछ नया थोपने का प्रयास करता है, जबकि सच्चाई यह है कि अधिकांश राज्यों के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों का अस्तित्व गहरे संकट में है। नवाचार का अर्थ यह नहीं होता कि मौलिक आवश्यकताओं की उपेक्षा कर दी जाए। शिक्षकों की अनुपलब्धता, अधोसंरचना की कमी, और पाठ्यक्रम की असंगतता जैसी समस्याएं बजट के अभाव में, नीति की गहराई नहीं, उसकी अस्थिरता और अदूरदर्शिता को उजागर करती हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार व सुदृढ़ता की बात करें तो वैश्विक संदर्भ में फ़िनलैंड जैसे देश स्थायित्व, शिक्षक स्वायत्तता और बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण के कारण उत्कृष्ट परिणाम दे पाए हैं। वहाँ शिक्षा में लगातार प्रयोग नहीं, सुसंगत नीति और समाज-सरकार की साझेदारी है। साथ ही स्थायी और समन्वित नीति ढांचे की, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों का ध्यान हो। शिक्षकों को नीति-निर्धारण में भागीदार बनाने की, न कि केवल क्रियान्वयनकर्ता। नवाचार और मूलभूत स्थिरता में संतुलन की-ताकि प्रयोग 'अति' बनकर मूल उद्देश्य को ही न खा जाए।

सरकार को यह समझना होगा कि शिक्षा कोई राजनीतिक प्रयोगशाला नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। विश्वगुरु वही बन सकता है, जो अपने बालकों को ज्ञान, जिज्ञासा और मूल्य के साथ शिक्षित करे-न कि केवल नीति के आंकड़ों से। इसलिए शिक्षा में 'अति-प्रयोग' नहीं, 'गंभीर प्रतिबद्धता' की ज़रूरत है। अति हर कार्य की बुरी होती है। सरकार को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विभिन्न प्रयोगों व बदलावों की अति से बचना चाहिए तथा शिक्षा क्षेत्र में सुदृढ़ व स्थायी सुधार की ओर ध्यान देना होगा। तब ही हम एक बार फिर शिक्षा के माध्यम से विश्व गुरू बन सकते हैं।

भारत के बीजों पर मंडराता खतरा

प्लांट ट्रीटी बैठक

नीलेश देसाई

लेखक कृषि मामलों के जानकर हैं।

पेरू में पौधा आनुवंशिक संसाधन खाद्य और कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत बहुपक्षीय प्रणाली (एमएलएस) को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण बैठक 7 जुलाई से शुरू हो रही है। इस बैठक में सह-अध्यक्षों के प्रस्ताव (प्रपोजल फॉर को चेयर्स) नामक एक नया पैकेज ऑफ मेजर्स अंतिम रूप लेने वाला है। इन सह-अध्यक्षों में भारत के डॉ. सुनील अर्चक भी शामिल हैं। यह स्थिति भारत की जैव विविधता और किसानों के अधिकारों के लिए एक गंभीर मोड़ है, जहाँ कॉर्पोरेट हितों का पलड़ा भारी होता दिख रहा है।

यह प्रस्तावित पैकेज ऑफ मेजर्स केवल वैश्विक बीज साझाकरण का मसौदा नहीं, बल्कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमारे पौधों के आनुवंशिक संसाधनों (यानी, बीज) और उनसे जुड़ी डिजिटल जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करने का एक छिपा हुआ एजेंडा है।

किसानों के हक़ पर हमला और पेटेंट का खतराः प्रस्तावित बदलावों से सभी पौधों के आनुवंशिक संसाधन एमएलएस के दायरे में आ जाएँगे, जिसका अर्थ है कि भारत को अपनी अनमोल जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर साझा करना होगा, अपनी शर्तों पर नहीं।

बड़ी कंपनियाँ इन देसी बीजों और आनुवंशिक सामग्री को आसानी से ले सकेंगी, उन पर पेटेंट या अन्य बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) हासिल कर सकेंगी। इसका सीधा असर हमारे किसानों पर पड़ेगा, जिन्हें भविष्य में अपने ही पारंपरिक बीजों का उपयोग करने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। यह पीढ़ियों से चले आ रहे किसानों के 'बीज बचाने, उपयोग करने, विनिमय करने और बेचने के मौलिक अधिकार पर सीधा हमला है।'

डिजिटल बायोपायरेसी का नया मोर्चाः सबसे खतरनाक पहलू डिजिटल अनुक्रम जानकारी (डीएसआई) या आनुवंशिक अनुक्रम डेटा (जीएसडी) को इस पैकेज में शामिल न करना है। कंपनियाँ बिना भौतिक बीज के ही उनके डिजिटल जेनेटिक डेटा तक पहुँच सकती हैं। यह उन्हें आसानी से नई किस्में विकसित करने और उन पर आईपीआर लेने की अनुमति देगा, जिससे डिजिटल बायोपायरेसी का एक नया और अप्रतिबंधित रास्ता खुल जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों और किसानों को बाद में इस जानकारी तक पहुँच से वंचित किया जा सकता है, जबकि उनकी अपनी जैव विविधता का शोषण हो रहा होगा।

जैव संप्रभुता का ह्रास और लाभ-साझाकरण की अनदेखीः एमएलएस में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। साझा किए गए बीजों की कोई प्रभावी 'ट्रैकिंग' नहीं है। इसका मतलब है कि भारत के मूल्यवान आनुवंशिक संसाधन, जिनमें किसानों के बीज भी शामिल हैं, एक ऐसे मंच पर पहुँच सकते हैं जहाँ कोई भी उन्हें ले जाकर व्यावसायिक लाभ कमा सकता है, बिना भारत सरकार या मूल किसान समुदायों की पूर्व सूचित सहमति के।

लाभ-साझाकरण की आवश्यकताओं से बचना भी आसान हो जाएगा, खासकर तब जब इन संसाधनों का गैर-खाद्य या गैर-पशु चारा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

प्रस्तावित गोपनीयता खंड पारदर्शिता को और कम करेंगे, जिससे राज्य और किसान यह जान भी नहीं पाएंगे कि उनके बीजों का क्या हो रहा है।

भारत की चुप्पी और किसानों की अनदेखीः यह और भी चिंताजनक है कि भारत, जो इस कार्यकारी समूह का सह-अध्यक्ष है, ने अभी तक इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर देश के किसानों, राज्य सरकारों और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जैसे संबंधित विभागों के साथ कोई राष्ट्रव्यापी परामर्श नहीं किया है। भारत के डॉ. सुनील अर्चक की सह-अध्यक्षता ऐसे प्रस्तावों को आगे बढ़ा रही है, जिन पर देश के अंदर कोई व्यापक चर्चा नहीं हुई है।

भारत को अपनी समृद्ध जैव विविधता और अपने किसानों के हितों की रक्षा करनी होगी। पूरी दुनिया के बीज क्षेत्र का केवल 1 प्रतिशत एफएओ के लाभ-साझाकरण कोष में दान करने के बदले में हमारी पूरी आनुवंशिक संपदा को एमएलएस के लिए खोल देना भारत और वैश्विक दक्षिण की खाद्य संप्रभुता और खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।

अब क्या? किसानों और जैव विविधता प्रेमियों की पुकार क्या है?

यह हमारे किसानों के पारंपरिक ज्ञान, उनकी मेहनत और उनके अधिकारों पर सीधा हमला है। हमें भारत सरकार से अपील करनी होगी कि-

वह इस प्रस्तावित पैकेज ऑफ मेजर्स को तुरंत अस्वीकार करे, खासकर अनुबंध 1 के विस्तार के प्रस्ताव को।

बीजों की चोरी और कॉर्पोरेट पेटेंट से सुरक्षा के लिए सख्त और प्रभावी प्रावधान लागू करे।

किसानों के संगठनों, विशेषज्ञों और राज्य सरकारों के साथ तत्काल और व्यापक परामर्श बैठकें आयोजित करे, ताकि भारत की एक संतुलित और सूचित राष्ट्रीय स्थिति तैयार की जा सके।

जैव विविधता और कॉर्पोरेट मुनाफे के बीच संतुलन बनाना आज की सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे बीजों पर हमारा नियंत्रण, हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है।

एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ

बैतूल। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के मेरा युवा भारत बैतूल के तत्वावधान में एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ सोमवार को कार्यालय कलेक्टर सभागार से किया गया। इस अभियान का शुभारंभ कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षत जैन के करकमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं आमजन भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला युवा अधिकारी श्रीमती सुषमा गवली, लेखा एवं कार्यक्रम पर्यवेक्षक सी. आर. जंघेला, तथा धनंजय सिंह ठाकुर की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने अभियान की सराहना करते हुए पौधरोपण की महत्ता पर प्रकाश डाला। अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम के अंतर्गत पौधे रोपने की जानकारी प्रदान की गई तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। अभियान का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ मातृ सम्मान को भावनात्मक रूप से जोडऩा है। कार्यक्रम में युवाओं से अपील की गई कि वे इस अभियान से जुडक़र अधिकाधिक संख्या में पौधे लगाएं और उन्हें सुरक्षित भी रखें।

प्रेमगढ़ आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर होगा गुरु पूजन

बैतूल। प्रेमगढ़ आश्रम कोसमी में इस वर्ष भी 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा पर्व पर गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन प्रेम स्वामी महाराज वृंदावन वाले के सानिध्य में संपन्न होगा। इस अवसर पर प्रेम स्वामी महाराज के शिष्य प्रेमगढ़ आश्रम पहुंचते हैं। वर्ष में एक बार प्रेम स्वामी महाराज के दर्शन, सेवा दान करने की भावना से शिष्य यहां एकत्र होते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस पर्व पर प्रेम स्वामी महाराज गुरु भक्ति का पाठ, प्रेम, धर्म की दीक्षा देंगे। उनके अनुसार यही मार्ग मानव देह के उद्धार का माध्यम है। इस मौके पर बंसीदास महाराज, राधा दास महाराज एवं सखी श्यामा जी ने समस्त श्रद्धालुजनों से अपील की है कि वे इस पुण्य अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में आकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। गुरु पूजन कार्यक्रम के उपरांत सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई है।

सड़क हादसे में ग्राम कोटवार की मौत

- बैंक से लौटते समय अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

बैतूल। सड़क हादसे में 25 वर्षीय ग्राम कोटवार अलकेश बिसोने की मौत हो गई। अलकेश बाइक से चिरापटला बैंक से पैसे निकालने गए थे। लौटते वक्त दोपहर में एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद राहगीरों ने उन्हें एंबुलेंस से चिचोली अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जांच प्रभारी दिनेश निमोडा ने बताया कि अलकेश की हालत को देखते हुए उन्हें भोपाल रेफर किया गया था, लेकिन परिजन उन्हें बैतूल के एक निजी अस्पताल ले गए। जहां रात करीब 3 बजे आईसीयू में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। मामले की मर्ग डायरी चिचोली थाना भेजी है।

नगरपालिका की स्वच्छता टीम ने शहर की सड़कों को किया चकाचक

- भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के जुलूस के बाद हुए कचरे को किया साफ

बैतूल। प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद हेमंत खण्डेलवाल का रविवार को प्रथम नगर आगमन हुआ। इस दौरान सोनाघाटी के फॉरेस्ट बैरियर से चक्कर रोड होते हुए जुलूस ने नगर में प्रवेश किया। श्री खण्डेलवाल का चक्कर रोड से लेकर बीजेपी कार्यालय तक जगह-जगह स्वागत किया गया। इस दौरान फूल माला और जिलेटिन इधर-उधर सडक़ पर भारी मात्रा में बिखर गई थी, जिससे सडक़ पर कचरा ही कचरा हो गया था। नगर पालिका सीएमओ सतीष मटसेनिया के मार्गदर्शन में स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनेलिया के निर्देशन में स्वच्छता टीम ने चंद घंटों में ही सडक़ों को साफ कर दिया। स्वच्छता निरीक्षक संतोष धनेलिया ने बताया कि आगे-आगे जुलूस चल रहा था, वहीं पीछे-पीछे नगरपालिका की सफाई कर्मियों की टीम भारी बारिश में सडक़ को जहां साफ कर रही थी। वहीं कचरा गाडिय़ों में कर्मचारियों द्वारा कचरा डाला जा रहा था, जिससे चंद घंटों के भीतर ही जहां-जहां से जुलूस निकला था, उस सडक़ को चकाचक कर दिया गया।

जिले में खरीदी के लिए बनाए हैं 20 केन्द्र बारिश ने भी किसानों को रोका रास्ता

पहले दिन मूंग-उड़द लेकर खरीदी केन्द्र नहीं पहुंचे किसान

संजय द्विवेदी, बैतूल। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई है। खरीदी के पहले दिन किसी भी केंद्र पर किसान उपज लेकर नहीं पहुंचे, जबकि इस साल समर्थन मूल्य में मूंग और उड़द बेचने के लिए जिले भर के कुल 5161 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं जिले में जहां पंजीयन के लिए 34 केन्द्र बनाये थे, वहीं खरीदी के लिए 20 केन्द्र बनाये है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में निर्णय लेते हुए ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द को समर्थन मूल्य पर खरीदी का निर्णय लिया है। समर्थन मूल्य में मूंग एवं उड़द खरीदी के लिए 19 जून से पंजीयन शुरू हुए थे और 5 जुलाई तक किसानों ने अपना पंजीयन कराया। वहीं 7 जुलाई से खरीदी शुरू की गई है। इस साल शासन द्वारा 8682 रु. प्रति क्विंटल के भाव से मूंग की खरीदी की जाएगी। शनिवार तक जिले के कुल 5161 किसानों ने पंजीयन करा लिया है, जोकि रकबे के हिसाब से 13501 हेक्टेयर है। उल्लेखनीय है कि इस बार जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग लगभग 15900 हेक्टेयर रकबे में बोई गई थी और बड़े पैमाने पर मूंग का उत्पादन भी हुआ है। समर्थन मूल्य में मूंग-उड़द की खरीदी की घोषणा के बाद मंडी में भी मूंग-उड़द के दामों में उछाल आया है। सोमवार को कृषि उपज मंडी बडोरा में मूंग की 81 बोरे की आवक रही, जबकि मूंग का न्यूनतम भाव 5501 और अधिकतम भाव 8 हजार रहा। वहीं उड़द की 10 बोरे आवक रही और न्यूनतम भाव 5400 एवं अधिकतम भाव 6101 रुपये था।

जल्द ही किसानों के केंद्र पहुंचने की संभावना: जिले में मूंग-उड़द की समर्थन मूल्य में खरीदी शुरू हो चुकी है, लेकिन पहले दिन कोई भी किसान अपनी उपज लेकर केन्द्र नहीं पहुंचा। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सोमवार को सुबह से बारिश का दौर जारी रहा। जिससे उपज भीगने की संभावनाओ को देखते हुए भी किसान केन्द्र नहीं पहुंचे। उम्मीद है कि जैसे ही बारिश कम होगी, किसान उपज लेकर केन्द्र पहुंचने लगेंगे। हालांकि इस साल पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक किसानों ने मूंग और उड़द बेचने के लिए पंजीयन कराया है। जिससे इस बार समर्थन मूल्य में मूंग की बेहतर खरीदी होने की उम्मीद है।

पिछले साल 3059 किसानों ने बेचा था मूंग: जिले में पिछले साल 3059 किसानों ने समर्थन मूल्य में मूंग बेचा था। हालांकि पिछले साल 3697 किसानों ने पंजीयन कराया था, किन्तु 638 किसानों ने मूंग नहीं बेचा। वहीं 3059 किसानों से 6630 एमटी (मेट्रिक टन) मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीदी हुई थी। जबकि इस साल मूंग-उड़द को मिलाकर कुल 5161 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। जिसमें से उड़द के लिए 36 किसानों ने पंजीयन कराया है, वहीं 5125 किसानों ने मूंग बेचने के लिए अपना पंजीयन केंद्रों पर कराया है।

जिले में बनाये 34 केंद्र, घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में सबसे अधिक: इस बार 15900 हेक्टेयर में किसानों ने मूंग लगाई थी। कुछ किसानों ने सरकारी खरीदी नहीं होने के कारण मूंग मंडी में बेच दी है। वहीं कई किसान समर्थन मूल्य में मूंग की खरीदी का रास्ता देख रहे थे। आखिरकार किसानों की मांग पूरी हुई और सरकार ने मूंग-उड़द को समर्थन मूल्य में खरीदी की घोषणा की। जिसके बाद जिले में मूंग-उड़द खरीदी के लिए 20 केन्द्र बनाये गये है। जिले में सहकारी समिति आठनेर, सहकारी समिति हिडली, आमला, जम्बाड़ा, रानीपुर, प्राथमिक चोपना, घोड़ाडोंगरी, कुरी रानीपुर, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित सारणी, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित पाढर, प्राथमिक सहकारी समिति मर्यादित चिचोली सहित जिले के अन्य ब्लॉकों में 20 केंद्र बनाए हैं। सबसे अधिक केंद्र घोड़ाडोंगरी ब्लॉक में बनाए गए हैं।

पिछले साल 8682 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा था मूंग: इस साल सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8768 रुपए तय किया है, जबकि पिछले वर्ष 2024-25 में 8682 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग की खरीदी की थी। वहीं मंडी में किसानों को मूंग के दाम 6 से साढ़े 7 हजार रुपए तक मिल रहे है। जिससे किसानों को एक से डेढ़ हजार रूपए प्रति क्विंटल नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब समर्थन मूल्य में मूंग-उड़द की खरीदी शुरू होने से किसानों को मूंग-उड़द के अच्छे दाम मिलेगे। मंडी में दाम कम मिलने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा था। लेकिन अब सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी से किसानों में खुशी का माहौल है।

इनका कहना है -

... सोमवार से मूंग-उड़द की खरीदी शुरू हो गई है। जिसके लिए जिले में 20 खरीदी केन्द्र बनाये है। हालांकि पहले दिन किसी भी केंद्र पर खरीदी की जानकारी नहीं है। बारिश के कारण भी किसान मूंग-उड़द लेकर नहीं पहुंचे है। जल्द ही किसानों के उपज लेकर केन्द्र आने की उम्मीद है।

- आनंद बडोनिया, उप संचालक, कृषि विभाग बैतूल

रैली एवं सभा में जेब काटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 जेब कतरे गिरफ्तार

बैतूल। कोतवाली पुलिस ने रैली एवं सभा में जेब कटिंग करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 जेब कतरो को गिरफ्तार किया है। पुलिस जनसंपर्क अधिकार से मिली जानकारी के अनुसार 6 जुलाई को संजय वर्मा पिता श्याम सुन्दर वर्मा निवासी सोहागपुर ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट किया कि दोपहर करीब 1.30 बजे नव नियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रथम बार नगर आगमन पर स्वागत के लिये भारत भारती के पास खडे थे, मौके पर काफी भीड थी। स्वागत समारोह के पास किन्ही अज्ञात व्यक्तियों ने मेरी पेंट की पीछे की जेब से 15 हजार रूपये निकाल लिये है। रिपोर्ट पर धारा 304(2), 3(5) बीएनएस का अज्ञात आरोपियो के विरूध्द कायम कर विवेचना में लिया गया। इस प्रकार 14 जून को फरियादी सारिक खान पिता अब्दुल कबीर निवासी चन्द्रशेखर वार्ड सदर बैतूल ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट किया कि केन्द्रीय राज्य मंत्री के प्रथम बार नगर आगमन पर स्वागत के लिये कारगिल चौक बैतूल में शाम 6.00 बजे खडे थे मौके पर काफी भीड थी स्वागत समारोह के पास किसी अज्ञात व्यक्ति ने मेरे कुर्ते के दाहिने जेब से 8 हजार 5 सौ रूपये निकाल लिये है। रिपोर्ट पर धारा 379 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूध्द कायम कर विवेचना में लिया गया। थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये रैली एवं सभा के आसपास सिविल वर्दी में पुलिस कर्मियो को तैनात किया गया। रैली से 4 संदिग्ध व्यक्तियो को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होने अपना जुर्म स्वीकार किया। आरोपियो ने पूछताछ पर 1 वर्ष पूर्व केन्द्रीय मंत्री की स्वागत रैली में कारगिल चौक पर भी जेब कटिंग करने की बारदात को स्वीकार किया गया है।

आरोपी आयुष पांडे पिता सुरेश पांडे 28 साल निवासी दमोह नाका जबलपुर, राहुल अग्रवाल पिता महेश अग्रवाल उम्र 33 साल निवासी साई नगर थाना मोहन नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ, किशोर कुमार सेन पिता रमेश सेन 32 साल निवासी दुर्गापारा सुपेला भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ और नीलेश मेश्राम पिता चिन्ताराम मेश्राम उम्र 33 साल निवासी सुपेला लक्ष्मी नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 13 हजार रूपये नगद जप्त कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस कार्रवाही में निरीक्षक रविकांत डेहरिया, उनि पंचम सिंह उईके, सउनि कमल किशोर बाथरे, आर. नितिन चौहान, प्र आर तरुण पटेल, प्र आर शिव कुमार, आर. अनिल वेलवंशी और आर. महेश नगदे की सराहनीय भूमिका रही।

गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में शास्त्रीय गायन एवं कथक समूह नृत्य से सजेगी शाम

गुरु के प्रति आदर प्रकट करने की सांस्कृतिक पहल के अंतर्गत शा.संगीत महा. एवं शा.ललित कला महा.धार का प्रतिष्ठित आयोजन

धार। मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग के सौजन्य से विगत् वर्षों की भांति इस वर्ष भी गुरु पुर्णिमा पर्व के अवसर पर 9 जुलाई बुधवार को, प्रातः 11 बजे से चित्रकला पर डेमॉन्स्ट्रेशन तथा 10 जुलाई गुरुवार को प्रातः 11 बजे व्याख्यान शा. ललित कला महाविद्यालय घोड़ा चौपाटी धार में तथा 12 जुलाई शनिवार संध्या 6 बजे से शास्त्रीय गायन एवं कथक समूह नृत्य विक्रम ज्ञान मंदिर, लालबाग में संगीत सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्राचार्य, शा. संगीत एवं शासकीय ललित कला महाविद्यालय धार ने बताया कि महाविद्यालय द्वारा आयोजित चित्रकला पर व्याख्यान एवं डेमॉन्स्ट्रेशन प्रख्यात चित्रकार सिद्धार्थ शिंगाड़े, मुंबई द्वारा होगा। 'संगीत समारोह' में शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करेंगे सुप्रसिद्ध गायक विजय सप्रे,भोपाल एवं अंतरराष्ट्रीय कथक नृत्यांगना डॉ. वी. अनुराधा सिंह , भोपाल, कथक समूह नृत्य प्रस्तुत करेंगी। श्रोताओं, दर्शकों व संगीत रसिकजनों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा।

बाबा श्याम की भक्ति में डूबा सोनोली धाम

एकादशी पर किया कोलकाता का श्रृंगार

बैतूल। देव शयनी एकादशी के पावन अवसर पर मुलताई के सोनोली धाम स्थित श्याम बाबा के मंदिर में भव्य कीर्तन संध्या का आयोजन हुआ, जहां कोलकाता के अलौकिक श्रृंगार में सजे बाबा श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भजन, भक्ति और भव्यता का ऐसा संगम देखने को मिला कि हर भक्त की आंखें श्रद्धा से छलक उठीं। इस अवसर पर मंदिर को कोलकाता से मंगवाए गए अलौकिक दिव्य श्रृंगार से सजाया गया। श्रृंगार अत्यंत मनोहारी था। बैतूल जिले का यह पहला बाबा श्याम का मंदिर है, जहां हर एकादशी को नियमित रूप से भव्य कीर्तन और भजन संध्या का आयोजन होता है। भजन संध्या में शैलेंद्र डोंगरे, बिंदेश मासोदकर, दीक्षा मासोदकर, अनुष्का विश्वकर्मा, मनु बंदेवार, पिंकी यादव और रिंकी यादव ने बाबा श्याम के भजनों की दिव्य प्रस्तुति देकर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन संध्या की हर एक प्रस्तुति पर भक्तों ने तालियों और जयकारों से वातावरण को भक्तिरस में सराबोर कर दिया।

आशा, उषा, सहयोगी संगठन का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया से मिला, दिया ज्ञापन

धार। मध्य प्रदेश की आशा कार्यकर्ता,उषा, आशा सहयोगी संगठन नई दिल्ली पहुंचकर संचार भवन नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिया । प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने सिंधिया जी को अवगत कराया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 29 जुलाई 2023 को भोपाल के लाल परेड मैदान में आशा कार्यकर्ता की महापंचायत रखी गई थी । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हजार रुपए प्रति साल बढ़ाने की घोषणा की थी वह अभी तक नहीं मिल मिला उसे शीघ्र दिलवाया जाए ।अ शा एवं आशा पर्यवेक्षक को सरकारी कर्मचारी मान्य किया जावे। आशा पर्यवेक्षक को लैपटॉप दिलाया जावे, आशा कार्यकर्ता को 6000 की जगह 12000 दिया जाए। आशा पर्यवेक्षक को 15 हजार की जगह 30 हजार दिया जाए । चर्चा के दौरान केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने आशा कार्यकर्ता उषा आशा सहयोगी संगठन की मांगों के निराकरण की बात करते हुए संगठन को बताया कि जल्द से जल्द ही आपकी मांगों को पुरा करवाने का प्रयास किया जाएगा । इस अवसर पर आशा उषा कार्यकर्ता संगठन की धार जिला अध्यक्ष संगीता मारू ने बताया कि चर्चा के दौरान प्रदेश अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव कविता सैनी ,ममता खिलची, धार ब्लॉक अध्यक्ष किरण भोंसले, धार अनीता शर्मा, बदनावर ब्लॉक अध्यक्ष कौशल्या पाटीदार ,बदनावर माया चौहान ,आदि उपस्थित थे। जानकारी संगठन के इंदौर संभागीय अध्यक्ष शंकर लाल मारू मोयाखेड़ा ने दी।

उद्योगों की रफ्तार बढ़ाने बैतूल बना बदलाव की प्रयोगशाला

- लघु उद्योगों को मिला नई सोच और सशक्त रणनीतियों का मंच
- बीआरसी क्लब में हुई आरएएमपी योजना पर आधारित कार्यशाला
- विशेषज्ञों ने दी लीन मैनेजमेंट, जेड सर्टिफिकेशन व औद्योगिक नीति की जानकारी

बैतूल। देश के निर्माण में रीढ़ माने जाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अब नए भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है। बैतूल में 7 जुलाई को आयोजित हुई एमएसएमई विभाग की कार्यशाला में जहां उद्योगों की कार्यप्रणाली में बदलाव की राह दिखाई गई, वहीं उनकी उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया गया। यह आयोजन बैतूल में उद्योगों के नवजागरण की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम साबित हुआ। एमएसएमई विभाग की नोडल एजेंसी, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम द्वारा बीआरसी क्लब, ग्रीन सिटी, बैतूल में इस एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन लघु उद्योग भारती इकाई बैतूल के सक्रिय सहयोग से किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जन अभियान परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहन नागर (राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त) उपस्थित रहे। वहीं विशेष अतिथियों में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधाकर पवार, भोपाल से पधारे लघु उद्योग विशेषज्ञ डीडी सेठिया, पुरुषोत्तम कौशिक, विनोद नायर, देवेंद्र श्रीवास्तव, प्रमुख उद्योगपति मुकेश खंडेलवाल, बालाराम साहू, हाकम सिंह रघुवंशी एवं बड़ी संख्या में लघु उद्योग भारती के सदस्य एवं जिले के उद्योगपति मौजूद रहे।

उद्योग विभाग के महाप्रबंधक ने दी कार्यशाला के उद्देश्य की जानकारी: जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के महाप्रबंधक धीरज मंडलोई ने कार्यशाला के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में एमएसएमई के माध्यम से उद्योगों की कार्यप्रणाली को प्रभावी और प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु आरएएमपी कार्यक्रम के अंतर्गत यह कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें लीन मैनेजमेंट, जेड सर्टिफिकेशन और नवीन औद्योगिक नीति जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। लघु उद्योग भारती के प्रदेश अध्यक्ष अंबेश बलुआपुरी ने अपने वक्तव्य में संगठन की कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि लघु उद्योग भारती देश का सबसे बड़ा ऐसा संगठन है जो लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहा है।

प्रशिक्षकों ने उद्यमियों से संवाद कर बताई सरकार की योजनाएं: लघु उद्योग भारती बैतूल सचिव राजा साहू ने जानकारी दी कि कार्यशाला में जेड पॉलिसी के प्रशिक्षक राजीव दलेला, आरएएमपी प्रशिक्षक सुदीप शहाणे एवं डीआईसी प्रशिक्षक देवेंद्र रघुवंशी द्वारा विस्तारपूर्वक प्रेजेंटेशन और मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त विनोद नायर, श्री सेठिया और श्री कौशिक ने भी उद्यमियों से संवाद करते हुए उन्हें सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एमएसएमई क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए आवश्यक है कि लघु उद्योग समय के साथ अपने कार्य पद्धति को सुधारें, उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाएं तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करें। कार्यक्रम के अंत में लघु उद्योग भारती बैतूल इकाई के वरिष्ठ पदाधिकारी अब्दुल हक ने सभी अतिथियों, वक्ताओं और उद्यमियों का आभार व्यक्त किया। कार्यशाला के सफल आयोजन में लघु उद्योग भारती बैतूल के सभी सदस्यों का सहयोग सराहनीय रहा।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी प्रेरणा से जन्मा 'ग्राम्या' गांव से राष्ट्र निर्माण की यात्रा

डॉ. पंकज शुक्ला

भोपाल। भारत के महान राष्ट्रनायक और भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर समाजसेवी डॉ. पंकज शुक्ला ने 'ग्राम्या' संस्था की स्थापना की है। यह संस्था ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने के लक्ष्य के साथ समर्पित रूप से कार्य कर रही है। 'ग्राम्या' के अध्यक्ष और सीएमडी डॉ. पंकज शुक्ला – जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं – ने कहा, डॉ. मुखर्जी केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक जीवंत विचारधारा के प्रतीक थे। उनके सिद्धांत हमें सिखाते हैं कि राष्ट्र की एकता, सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी स्वावलंबन के लिए संगठित और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। डॉ. शुक्ला ने बताया कि 'ग्राम्या' की स्थापना ग्रामीण भारत को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से की गई है।

यह संस्था गांवों में स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण, कृषि नवाचार, जैविक खेती, पोषण अभियान और स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अनेक कार्यक्रम संचालित कर रही है। उनका मानना है कि डॉ. मुखर्जी का बलिदान भारत की एकता और आत्मगौरव का प्रतीक है। उसी विचारधारा को धरातल पर उतारने का प्रयास 'ग्राम्या' के माध्यम से हो रहा है। जब गांव मजबूत होंगे, तभी राष्ट्र सशक्त होगा।

'ग्राम्या' द्वारा नारी शक्ति - राष्ट्र शक्ति, स्वदेशी को सम्मान और हर गांव बने आत्मनिर्भर केंद्र जैसे राष्ट्रवादी अभियानों का संचालन किया जा रहा है।

ये कार्यक्रम सेवा, संस्कार और स्वावलंबन जैसे मूल्यों पर आधारित हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रेरणास्रोत विचारधारा से जुड़ाव रखते हैं। डॉ. शुक्ला ने कहा, डॉ. मुखर्जी के 'एक देश - एक विधान' जैसे सिद्धांतों की तर्ज पर आज जरूरत है कि भारत के हर गांव को समान अवसर और विकास का अधिकार मिले। यही आज का राष्ट्रधर्म है। डॉ. पंकज शुक्ला के नेतृत्व में 'ग्राम्या' ने राष्ट्र निर्माण को ज़मीनी स्तर पर साकार करने की दिशा में एक वैचारिक आंदोलन का रूप ले लिया है।

यह मात्र एक एनजीओ नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण की पहल है – जिसमें हर गांव, हर महिला और हर युवा को देश की विकास यात्रा में भागीदार बनाया जा रहा है। डॉ. शुक्ला ने कहा, डॉ. मुखर्जी की तरह हमें भी सत्ता नहीं, सेवा का मार्ग चुनना होगा। जब भारत का हर गांव जागरूक और आत्मनिर्भर बनेगा, तभी हमारा देश सच्चे अर्थों में विश्वगुरु कहलाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज की अध्यक्षता में आईसीएआर की 96वीं वार्षिक आम बैठक

कृषि राज्य का विषय है, कृषि के लिए राज्य सरकारों का सहयोग अपेक्षित : शिवराज सिंह

नईदिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर के भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की 96वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 18 से ज्यादा केंद्रीय एवं राज्य मंत्री शामिल रहें। कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जितेंद्र सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री श्री एस. पी. बघेल, मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, अरुणाचल के कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी मंत्री श्री ग्रेबियल डी. वांगसू, बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा, बिहार की पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री श्री रेनू देवी, मध्य प्रदेश के बागवानी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा, मिजोरम के कृषि मंत्री श्री पी. सी. वनलालरुआता, हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण व पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री श्याम सिंह राणा, उत्तर प्रदेश के पशुपालन व डेयरी विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह, कर्नाटक के कृषि मंत्री श्री एन. चेलुवरिया स्वामी, उत्तर प्रदेश के कृषि, शिक्षा, कृषि अनुसंधान मंत्री श्री सूर्यप्रताप शाही, ओडिशा के मत्स्य, व पशु संसाधन विकास विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गोकुलानंद मलिक, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री अदल सिंह कंसाना, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री श्री माणिराव कोकाटे एवं कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी उपस्थित थे।

इस बैठक में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम. एल. जाट ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन 2024-2025 का प्रस्तुतिकरण एवं अंगीकृत करने हेतु संकल्प पढ़ा। इसके बाद आईसीएआर के वित्तीय सलाहकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखा का प्रस्तुतीकरण दिया गया और इसे अंगीकृत करने हेतु संकल्प पढ़ा गया। बैठक में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 जारी की गई। साथ ही कृषि एवं प्रौद्योगिकी संबंधित चार पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसके तत्पश्चात् सभी मंत्रियों ने बैठक को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने भारत के खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को लेकर प्रसन्नता जाहिर की।

बैठक में सभी मंत्रियों ने एकस्वर में भविष्य में खेती और किसान समृद्धि की दिशा में एकजुट होकर सार्थक प्रयास करने की प्रतिबद्धता भी जताई। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री ने फसल औषधि केंद्र के विचार को आगे बढ़ाने की भी बात की। साथ ही विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से प्रसांगिक योजनाओं को जारी रखने और अप्रासंगिक योजनाओं को खत्म करने और नई योजनाओं के शुरू होने को लेकर सुझाव भी आमंत्रित किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों को मिल रहा है या नहीं, इसका निरीक्षण बेहद जरूरी है।

स्वास्थ्य अधोसंरचना विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

- **समयबद्धता, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता के साथ हो योजनाओं का क्रियान्वयन**

भोपाल। उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में विभागीय अधोसंरचना विकास कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक में राज्य योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, 15वां वित्त आयोग एवं प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की गई। उप

मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की प्रगति नियमित रूप से मॉनिटर की जाए और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि अप्रारंभ कार्यों की समयबद्ध शुरुआत सुनिश्चित की जाए तथा लंबित निविदाओं की प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि हर परियोजना की प्रोजेक्टवार समीक्षा की जाए और यह देखा जाए कि बजट के उपयोग में पारदर्शिता, समयबद्धता और उचित तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने निर्देश दिए कि प्रत्येक योजना की मासिक समीक्षा की जाए और कार्यों की प्रगति की फील्ड मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये। विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी लंबित कार्यों की समयसीमा निर्धारित कर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

तकनीकी मानव संसाधन की नियुक्ति शीघ्र हो

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने विभाग में रिक्त पड़े तकनीकी पदों (इंजीनियरिंग एवं सुपरविजन स्तर) की शीघ्र भर्ती के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए तकनीकी मैनपावर की तैनाती अत्यावश्यक है। प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री संदीप यादव, परियोजना संचालक श्री नीरज कुमार सिंह, एनएचएम की प्रबंध संचालक डॉ. सलोनी सिडाना, तथा विभागीय अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बताया गया कि अधोसंरचना विकास के 2949 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 1972 कार्य पूर्ण तथा 754 कार्य प्रगति पर हैं। चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 335 कार्यों का सफलतापूर्वक निष्पादन हुआ है। इन परियोजनाओं के लिए राशि रुपये 2483.37 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसके विरुद्ध अब तक राशि रुपये 729.52 करोड़ का व्यय हो चुका है। भोपाल में सर्वाधिक 480 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसमें 306 कार्य पूर्ण हुए हैं एवं रुपये 121.10 करोड़ व्यय किया गया है। जबलपुर संभाग ने रुपये 147.69 करोड़ के व्यय के साथ सर्वाधिक वित्तीय प्रगति दर्ज की है।

राज्य स्तरीय योजना मद के अंतर्गत 285 कार्य स्वीकृत, जिनमें 156 पूर्ण/हस्तांतरित एवं 118 कार्य प्रगति पर हैं। 9 कार्य अप्रारंभ हैं एवं 2 कार्य निविदा स्तर पर हैं। जबलपुर (रु 37.28 करोड़), भोपाल (रु 39.41 करोड़) और रीवा (रु 33.01 करोड़) सहित सभी संभागों में योजनाओं की सतत प्रगति जारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 669 कार्य स्वीकृत, जिनमें से 367 पूर्ण, 245 कार्य निर्माणाधीन, 10 निविदा स्वीकृत, 12 निविदा स्तर पर, एवं 35 कार्य अप्रारंभ हैं। अब तक राशि रुपये 164.69 करोड़ का व्यय किया गया है। उज्जैन में सर्वाधिक 183 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 104 पूर्ण हो चुके हैं। जबलपुर में रु 36.07 करोड़, भोपाल में रु 28.41 करोड़ और रीवा में रु 20.05 करोड़ का व्यय दर्ज हुआ है।

15वें वित्त आयोग मद में 1934 कार्य स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 146 कार्य पूर्ण, 206 कार्य निर्माणाधीन, 170 कार्य निविदा स्तर पर, एवं 141 कार्य अप्रारंभ हैं। इंदौर (331 कार्य) और जबलपुर (321 कार्य) में सर्वाधिक कार्य स्वीकृत हुए हैं, जहां क्रमशः रु 63.84 करोड़ एवं रु 66.01 करोड़ का व्यय हुआ है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-अभीम) अंतर्गत 61 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें 23 कार्य पूर्ण, 25 प्रगति पर, और 36 कार्य निविदा स्तर पर हैं। इनके लिए राशि रुपये 87.39 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है और अब तक राशि रुपये 46.80 करोड़ का व्यय किया गया है। भोपाल (9 कार्य), ग्वालियर (7), इंदौर (11), जबलपुर (14) में योजनाओं का क्रियान्वयन जारी है।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल का इंदौर के बायपास रोड स्थित एकजोटिका होटल में इंदौर ग्रामीण जिले के मऊ व सांवेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया। स्वागत समारोह को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खण्डेलवाल ने संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश शासन के मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, संभाग प्रभारी श्री राघवेन्द्र गौतम, पूर्व मंत्री व विधायक सुश्री उषा ठाकुर एवं इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्री श्रवण चावड़ा सहित बडी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने मंचों के माध्यम से उनका आत्मीय स्वागत किया। श्री खंडेलवाल ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया।

आयकर विवरणी के प्रारूप वेबसाईट पर अपलोड नहीं होने से लाखों करदाता परेशान

आयकर अधिनियम के प्रावधानो के तहत् वित्त वर्ष 2024-25 के लिए करदाताओं को 15 सितम्बर 2025 तक आयकर विवरणी एवं ऑडिट की पात्रता वाले करदाताओ को 30 सितम्बर 2025 तक ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है किंतु वित वर्ष की समाप्ति के लगभग सवा तीन माह बाद भी अभी तक आयकर विभाग द्वारा विवरणीयों के सारे प्रारूप एवं ऑडिट प्रारूप ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड नही किए गए है। जिससे देष के लाखो करदाता अभी तक अपनी विवरणीयां प्रस्तुत नही कर पा रहे है। नियमानुसार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को 1 अप्रैल को ही आयकर विवरणी के प्रारूप ई-फाइलिंग वेबसाईट पर अपलोड कर देना चाहिए ताकि करदाता अपनी विवरणी निर्धारित समय पर दाखिल कर सकें। विभागीय व्यवस्था के तहत् विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिए अलग-अलग प्रारूप आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक वित वर्ष के लिए जारी किए जाते है इस मर्तबा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा केवल प्रारूप 1 एवं 4 ही जारी किए गए है जो वेतन भोगी कर्मचारियों एवं अन्य स्त्रोत से आय प्राप्तकर्ता एवं आयकर अधिनियम की धारा 44-एडी, एई के तहत् आय दर्षाने वाले करदाताओं के लिए लागू होता है। लेकिन व्यवसाय से होने वाली आय एवं भागीदारी फर्म तथा कंपनी करदाताओं के लिए वांछित प्रारूप 2, 3, 5 एवं 7 तथा ऑडिट का प्रारूप भी अभी तक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड नही किया गया होने के कारण इस श्रेणी के करदाता अपनी विवरणी जमा नही करवा पा रहे है। अनेक करदाताओ को बैंक लोन सहित अन्य कार्यो के लिए वित वर्ष 2024-25 की विवरणी तथा ऑडिट रिपोर्ट की अनिवार्यता होती है लेकिन अभी तक प्रारूप जारी नही होने के कारण करदाताओं के कार्य रूके हुए है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत् जिन करदाताओं को ऑडिट की पात्रता नही आती है उन्हे 31 जुलाई 2025 तक विवरणी प्रस्तुत करना होती है लेकिन वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा इस तिथी को आगे बढाया जाकर 15 सितम्बर 2025 की अंतिम तिथी निर्धारित की गई है। साथ ही ऑडिट की पात्रता वाले करदाताओं को 30 सितम्बर 2025 तक ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। इन तिथीयों के पश्चात् विवरणी जमा करने अथवा ऑडिट करवाने पर करदाता को पेनल्टी का भुगतान करना होता है। किंतु वित्त वर्ष समाप्ति के सवा तीन माह बाद भी विवरणी एवं ऑडिट के प्रारूप केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड नही किए गए है यदि अभी भी प्रारूप ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड कर दिए जाते है तो करदाता को मात्र 2 माह का ही समय मिलेगा।

(बी. एल. जैन)

जबकि पुर्व वित वर्षो मे उसे अप्रैल से जुलाई तक अर्थात् 4 माह का समय मिलता था इसी तरह ऑडिट की पात्रता वाले करदाता को भी अब मात्र 3 माह का ही समय मिलेगा। वित वर्ष 2024-25 के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा विवरणी प्रस्तुती हेतु विस्तृत जानकारियां चाही गई है ऐसी स्थिती मे इतने कम समय मे करदाता एवं कर सलाहकारों तथा सी.ए. से जुड़े हुए प्रोफेषनल व्यक्तियों को समय कम मिलने के कारण अत्यधिक परेषानी उठाना पड़ेगी। यदि करदाता समय पर विवरणी नही जमा करवा पाता है तो उसे नियमानुसार पेनल्टी का भुगतान करना होगा। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से किए जा रहे विलंब का खामियाजा देष के लाखो करदाताओं को अनावष्यक रूप से उठाना पड़ेगा। ऐसी स्थिती मे केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को वांछित प्रारूप षिघ्रतापुर्वक जारी कर देना चाहिये तथा आगामी वितीय वर्षो के लिए भी 1 अप्रैल के पुर्व वांछित प्रारूप ई-फाईलिंग वेबसाईट पर अपलोड कर देना चाहिये क्योंकि सीबीडीटी के पास तो पुरा एक वर्ष का समय होता है ऐसा होने पर भविष्य मे करदाताओं को भी कोई परेषानी नही होगी तथा विवरणीयां जल्दी प्रस्तुत होने पर शासन को राजस्व की प्राप्ति भी शीघ्रतापुर्वक प्राप्त हो सकेगी।

दमोह में मिशन अस्पताल में

कार्डियोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रहे एक फर्जी डॉक्टर के मामले में कई अनियमितताएं मिलीं

भोपाल। अनुशंसाओं में 7 पीड़ित रोगियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि देने, डॉक्टर और अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के अलावा दोषी पुलिसकर्मियों और सीएमएचओ, दमोह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा राज्य सरकार को यह भी सत्यापित करने कहा गया कि क्या सभी डॉक्टर कैथ लैब में काम करने के लिए योग्य हैं या नहीं ईओडब्ल्यू और मुख्य आयकर आयुक्त (छूट), भोपाल से अस्पताल द्वारा आयुष्मान भारत योजना के दुरुपयोग की जांच कराने को कहा गया केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव से देशभर में कैथ लैब का सत्यापन कराने और आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन की जांच के लिए सभी राज्य सरकारों को निर्देश देने को कहा गया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने अपनी जांच के बाद मध्य प्रदेश के दमोह में मिशन अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे एक फर्जी डॉक्टर के मामले में कई अनियमितताएं पाई हैं। इसके अनुसार, आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र को कई अनुशंसाएं की हैं और चार सप्ताह के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने 28 मार्च, 2025 को एक शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया था और मामले पर संबंधित राज्य अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने के अलावा अपनी जांच भी की थी।

आयोग ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को अनुशंसा की है कि वह इस अस्पताल में फर्जी हृदय रोग विशेषज्ञ द्वारा इलाज के बाद मरने वाले सभी सात मरीजों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये की सहायता राशि दे। आयोग ने मामले के अंतिम निपटारे तक मिशन अस्पताल का लाइसेंस रद्द करने की भी सिफारिश की है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी कैथ लैब का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार यह सत्यापित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश जारी करेगी कि सभी डॉक्टर कैथ लैब में काम करने के लिए योग्य हैं या नहीं।

राज्य सरकार से की गई कुछ अन्य अनुशंसाएं इस प्रकार हैं-

- बताएं कि अस्पताल ने बीमा कराया था या नहीं? यदि हां, तो क्या मृतक पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारियों को बीमा राशि दी गई है या नहीं;
- क्या सर्जरी करने, रोगियों के मेडिकल इतिहास के बारे में विवरण और किसी भी प्रासंगिक परीक्षण के परिणाम या विशिष्ट प्रक्रिया, इसके संभावित जोखिम और लाभ और किसी भी वैकल्पिक उपचार के विकल्प के बारे में कोई जानकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ), दमोह के साथ साझा की गई थी;
- भूखंड क्रमांक 86/1 पर पट्टे, हस्तांतरण और अनधिकृत निर्माण से संबंधित अनियमितताओं की जांच करें और दोषी अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई शुरू करें;
- पुलिस महानिदेशक, मध्य प्रदेश को एफआईआर दर्ज करने और इसकी जांच में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने, मिशन अस्पताल के आरोपियों और प्रबंधन के खिलाफ प्रक्रियात्मक कानून और कानूनी सिद्धांतों के अनुसार अलग-अलग एफआईआर दर्ज करने और गैर इरादतन हत्या, धोखाधड़ी, ठगी, जालसाजी, चिकित्सकीय लापरवाही, कदाचार, धन की हेराफेरी आदि से संबंधित आरोप लगाने के लिए कहा गया है।

80 मेडिकल छात्राएं बोलीं- गंदा व्यवहार करते हैं डॉक्टर

रीवा में हरासमेंट का आरोप लगाया, अस्पताल के ईएनटी विभाग में काम बंद होने से प्रभावित

रीवा (नप्र)। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में 80 छात्राओं ने ईएनटी विभाग के चिकित्सक पर हरासमेंट के आरोप लगाए हैं। कहा कि डॉक्टर उनसे गंदा व्यवहार करता है, इसलिए वह उधर काम नहीं करेंगीं। छात्राओं ने कोलकाता के आरजी कॉलेज में हुए कांड को देखते हुए ड्यूटी करना बंद भी कर दिया। डॉक्टर की प्राचार्य से लिखित शिकायत के बाद। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी छात्राओं की ड्यूटी वहां हटा दी, जिसकी पुष्टि डीन ने की। इधर स्टूडेंट्स के न पहुंचने से मरीजों के इलाज में समस्या आ रही है। शिकायत के बाद डीन ने जांच कमेटी गठित की है, 7 दिन में वह रिपोर्ट सौंपेगी।

एक सप्ताह में प्रस्तुत होगा प्रतिवेदन

डीन डॉ सुनील अग्रवाल ने डॉ अशरफ के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले की जांच महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियमन 2013 के तहत गठित आंतरिक परिवाद समिति की टीम करेगी। इस टीम की पीठासीन अधिकारी नेत्र रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ शशि जैन हैं, वह अपनी टीम के साथ मामले की जांच करेंगी।जांच करने के बाद डीन को एक सप्ताह में जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी। इस जांच टीम में आंतरिक परिवाद समिति की पीठासीन अधिकारी डॉ शशि जैन, सदस्य डॉ नीरा मराठे, पीएसएम, श्रीमती रीना पटेल स्टाफ नर्स और अशासकीय सदस्य के रूप में कमलेश सचदेवा खुशी फाउंडेशन शामिल हैं। यही मामले की जांच करेंगे। डॉ सुनील अग्रवाल, डीन, श्यामशाह मेडिकल कॉलेज में बताया कि छात्राओं ने चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। प्रवीण पटेल, प्राचार्य नर्सिंग कॉलेज ने बताया कि छात्राओं की शिकायत पर उनकी सुरक्षा को प्राथमिक मानते हुए शिकायत की है और उनके ईएनटी विभाग में ड्यूटी पर रोक लगा दी है। जानकारी के मुताबिक ईएनटी विभाग वही विभाग है, जहां काम करने वालों वॉर्ड बॉय ने कुछ दिनों पहले वॉर्ड एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की वारदात को अंजाम दिया था। नाबालिग ने गैंगरेप के गंभीर आरोप भी लगाए थे। जिसमें जांच अभी चल रही है।

स्टूडेंट्स बोलीं- डॉक्टर करते हैं गंदा व्यवहार

नर्सिंग की 80 छात्राओं ने लिखित में कहा है कि डॉ अशरफ छात्राओं के साथ गंदा व्यवहार करते हैं। छात्राओं ने उनके व्यवहार और हाव भाव से खुद को असुरक्षित बताया है। पत्र में कहा है कि डॉ अशरफ का व्यवहार कई मर्तबा छात्र को मानसिक रूप से असहज, असुरक्षित और अपमानित करने वाला रहा है छात्राओं ने शिकायत में कहा है कि उनका व्यवहार मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसा है। उन्होंने शिकायत में कहा है कि डॉ अशरफ के व्यवहार के चलते क्लीनिकल लर्निंग वातावरण भी प्रभावित हो रहा है। इसके बाद प्राचार्य ने डीन को पत्र लिखकर चिकित्सक की हरकतों से अवगत कराया। छात्राओं को असुरक्षित देखते हुए प्राचार्य ने डीन से इस मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है।

डीन ने जांच दल गठित किया

प्राचार्य ने डीन को पत्र लिखा है। डीन ने मामले में तीन सदस्यीय जांच टीम बैठा दी है। माना जा रहा है की जांच कमेटी द्वारा अधिष्ठाता को दिए जाने वाले प्रतिवेदन के बाद चिकित्सक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि आरोप यह भी हैं उसी विभाग के लोगों को जांच सौंप दी गई है। संजय गांधी अस्पताल के चिकित्सक डॉ अशरफ पर इस बार शासकीय नर्सिंग कॉलेज की बीएससी नर्सिंग द्वितीय वर्ष की छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाकर हड़कंप मचा दिया है। इसकी लिखित शिकायत छात्राओं ने नर्सिंग कॉलेज प्राचार्य से की थी। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए प्राचार्य ने इस संबंध में डीन श्याम शाह मेडिकल कॉलेज को पत्र लिखकर अवगत कराया।

शहडोल में 3 हजार घरों में पानी घुसा

मंदसौर के गांधी सागर डैम में दो युवक डूबे

भोपाल (नप्र)। मध्यप्रदेश के कई जिलों में लगातार तेज बारिश होने की वजह से हालात बिगड़ने लगे हैं। राजस्थान के कोटा से पिकनिक मनाने गरोठ के भानपुरा आए दो युवकों की गांधी सागर डैम में डूबने से मौत हो गई। घटना रविवार शाम 7 बजे की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। आधी रात 3 हजार से ज्यादा घरों में पानी भर गया। यहां अस्पताल में पानी भर जाने पर मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा। रेलवे ट्रैक डूब जाने से 4 घंटे तक ट्रेन रूट बंद रहा। एनडीआरएफ की टीम रात 9 बजे घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 15 घंटे की सर्चिंग के बाद सोमवार सुबह 9 बजे दोनों के शव बरामद किए गए। मृतकों की पहचान सोनू यादव (20) और चेतन कुमार (24) के रूप में हुई है। डिंडौरी के मेहदवानी जनपद पंचायत क्षेत्र में धमनी-कुसेरा मार्ग बारिश से क्षतिग्रस्त हो गया है। तीन साल पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़क बनी थी। सड़क टूटने से इस रास्ते पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। भोपाल कई इलाकों में ट्रैफिक जाम

- बालाघाट के कई गांवों का सड़क संपर्क टूटा; डिंडौरी में धमनी-कुसेरा सड़क धंसी, भोपाल में झमाझम, 3 किलोमीटर लग गया था जाम

की स्थिति बन गई। भोपाल के एमपी नगर थाने से नर्मदापुरम रोड तक करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

सीहोर पार्वती और पपनाश नदी उफान पर

सीहोर जिले के पार्वती और पपनाश नदी भारी बारिश के चलते उफान पर हैं। पार्वती नदी पर हादसा होते-होते बचा। पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इस बीच कार चालक ने लोगों के मना करने के बाद भी कार नहीं रोकी और आगे जाकर वो फंस गई। लोगों ने कार सवार को बाहर निकाला।

मंडला में नर्मदा खतरे के निशान से पार

मंडला में पिछले 24 घंटे में हुई भारी बारिश से नर्मदा नदी का जलस्तर वॉर्निंग लेबल क्रॉस कर 437.40 मीटर पर पहुंच गया है। माहिष्मती घाट स्थित छोटा पुल फिर डूब गया है। साथ ही मटियारी, सुरपन, बंजर सहित कई नदियां उफान पर हैं। जबलपुर, उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट और अनूपपुर में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की छुट्टी कर दी गई है।

अनिल यादव व्यक्ति नहीं विचार थे, बासौदा के पर्याय थे : शिवराज

गंजबासौदा में प्रेस क्लब के पत्रकार भवन का लोकार्पण, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुनाए संस्मरण

गंजबासौदा। अनिल यादव व्यक्ति नहीं विचार थे, वो संस्था थे। वो गंजबासौदा के योद्धा थे। उन्होंने जनप्रतिनिधि न रहते हुए भी जनता की शक्ति का जनता के हित के लिए काम किया। अनिल भाई उपेक्षितों की आवाज बने। उन्होंने पेड़ों, खेत, नदी, जंगल की चिंता की। बेतवा, पाराशरी के संरक्षण का जिम्मा उठाया। उनके काम को हम कितना गिनाएं...।

यह बात केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। वे रविवार को गंजबासौदा में वरिष्ठ पत्रकार एवं पर्यावरणविद् स्वर्गीय अनिल यादव की स्मृति में प्रेस क्लब एवं नगर पालिका परिषद के सहयोग से नवनिर्मित अत्याधुनिक पत्रकार भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। मदन भैया क्लब पार्क के प्रांगण में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया उपस्थित रहीं। विशेष अतिथियों के रूप में गंजबासौदा विधायक हरिसिंह रघुवंशी, विदिशा विधायक मुकेश टंडन, कुरवाई विधायक हरिसिंह सप्रे, भाजपा जिलाध्यक्ष महाराज सिंह दांगी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. राकेश सिंह जादौन, नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव, जनपद अध्यक्ष नीतू देवेंद्र सिंह रघुवंशी सहित प्रदेश की अनेक हस्तियां उपस्थित रहीं।

यादव की स्मृति में रोपा बरगद का पौधा

कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण से हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अनिल यादव की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए परिसर में बरगद का पौधा रोपा। इस अवसर पर उन्होंने अनिल दाउ फाउंडेशन की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं के बीच पहुंचकर उनका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में श्री चौहान ने मध्यप्रदेश के करीब तीन दर्जन से अधिक वरिष्ठ पत्रकारों को प्रेस क्लब गंजबासौदा की ओर से शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

प्रेस क्लब ने किया सम्मान

इस अवसर पर मंचीय कार्यक्रम में सर्वप्रथम प्रेस क्लब अध्यक्ष नीतेश नायक, सचिव नरेश मीणा सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत एवं अभिनंदन किया। इसके पश्चात् नगर पालिका के पार्षदों ने अन्य अतिथियों का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श चौहान ने कहा, आज का कार्यक्रम मेरी जिंदगी में अलग महत्व रखता है। अनिल भाई मेरे दिल के कोने में

स्थान रखते हैं। ये उन दिनों की बात है, जब हम विद्यार्थी परिषद में थे। तब हम विद्यार्थी परिषद के चुनाव के लिए वोटरों की जुगाड़ कर रहे थे। उन्हीं दिनों में मेरी अनिल भाई से मुलाकात हुई थी। फिर बाद के दिनों में तो उनकी होटल नीलकमल हम छात्र नेताओं का स्थाई ठिया बन गई थी। भाभी जी (शशि यादव) आप आंखों में आंसू न लाएं। उनकी स्मृति आपकी ताकत है। उनके चित्र को सामने रखें और जनसेवा में अनवरत जुटी रहीं। कृषि मंत्री चौहान ने कहा, अनिल भाई राष्ट्रवादी चिंतक थे। विचारक और संगठक थे। अनिल भाई मेरे लिए बासौदा का पर्याय रहे। हमने खूब साथ में काम किया। वे चाहते थे शिखर पर पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मिट्टी को नहीं छोड़ा। वे जमीन से जुड़े रहे। मैंने उन्हें विभिन्न काम करते देखा। आज जब बरगद का पौधा लगाया तो उसमें बसने वाले पौधे, जीव जंतु याद आए। अनिल भाई इनकी चिंता करते थे। उन्होंने पेड़, जंगल, नदियों की खूब चिंता की। नरवाई पर उनकी आत्मा रोती थी।

गंजबासौदा के योद्धा थे अनिल भाई : शिवराज सिंह

अनिल भाई व्यक्ति नहीं, विचार थे, वे संस्था थे। वो गंजबासौदा के योद्धा थे। उन्होंने जनप्रतिनिधि न रहते हुए भी जनता की शक्ति का जनता के हित के लिए काम किया। अनिल भाई ने पेड़ों, खेत, नदी, जंगल की चिंता की। बेतवा, पाराशरी के संरक्षण का जिम्मा उन्होंने उठाया। उनके काम को हम कितना गिनाएं.... मैं कहां कहां से गुजर गया। उनके लेखों को आपने पढ़ा होगा, हमेशा ही उन्होंने उसमें चिंताएं गिनाईं। समाज से उपेक्षित पारधी उनके बच्चों की आवाज उन्होंने उठाई। उनका नेतृत्व कुशल था। उनके पास राजनीति और पत्रकारिता चुनने का मौका आया तो उन्होंने पत्रकारिता को प्राथमिकता दी। जब मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा उस समय उन्होंने सामने न आकर लोगों को जोड़ा। पर्यावरण के लिए उन्होंने काफी काम किया। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो फोन पर हमारी लगातार बात होती थी। लंबी चर्चा चलती थी। पर्यावरण को लेकर उनकी चिंता थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पर्यावरण के संरक्षण का जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अनिल भाई मैं पर्यावरण के लिए पेड़ लगाता रहा। मैं लगातार पेड़ लगाता हूं। अब तुम्हारा पर्यावरण आंदोलन बन गया। हर जन्मदिन पर लोग पेड़ लगाते हैं। हम तुम्हारे कामों को पूरा कर रहे हैं। अब तो आपकी अर्धांगिनी हमारे भाभी भी जनता के लिए काम करने लगी है। आप जहां भी हैं, उनकी शक्ति बढ़ाते रहना। शिवराज सिंह ने कहा, कोविड के समय अनिल भाई ने खूब सेवा की, लेकिन इस दौरान वो इंफेक्टेड हो गए। हमारी उम्मीद थे हम उन्हें बचा लेंगे लेकिन नहीं कर सके। कई बार भगवान बेदर्द हो जाता है। अच्छे लोगों को आपके पास बुला लिया। अभी तो हम सुनना चाहते थे, उनके साथ काम करना चाहते थे। अनिल भाई आपकी प्रेरणा थी पत्रकार भवन, ये भवन आपकी स्मृति है। संघर्ष के दिनों में अनिल भाई ने परिवार को संभाला। परिवार को कैसे चलाना चाहिए, इसका जीता जागता उदाहरण है उनका ये परिवार है। बासौदा वालों अपने लिए तो सब जीते हैं। दूसरों के लिए भी जिएं। सभी को साथ लेकर आगे चलते चलो, जीवन उसी का नाम है। अनिल भाई इतिहास छोड़कर गए हैं। उनके चरणों में मेरी श्रद्धांजलि।

विधायक ने सौंपा मांग पत्र

विधायक हरिसिंह रघुवंशी ने कहा, हम सब एक ऐसे व्यक्तित्व को स्मरण कर रहे हैं, जो केवल नाम नहीं, बल्कि विचार और आदर्शों की जीवंत मिसाल हैं... स्वर्गीय श्री अनिल यादव जी। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें नमन करते हुए उनके जीवन से सीख लेने का संकल्प लेते हैं। गंजबासौदा की पवित्र मिट्टी में जन्मे अनिल जी ने विद्यार्थी परिषद से छात्र राजनीति में नेतृत्व की शुरुआत की। छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने युवाओं की आवाज को बुलंद किया। उन्होंने हमेशा समस्याओं के साथ समाधान भी दिए। दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई कर 'जनसत्ता' से जुड़े और अपनी पैनी लेखनी से समाज को नई दृष्टि दी। उनकी कलम में जल, जंगल और जमीन बसते थे। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युगपुरुष को पहली बार गंजबासौदा लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है। इस अवसर पर विधायक श्री रघुवंशी ने केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को नगर विकास से जुड़ा मांग पत्र भी सौंपा।

अनिल भाईसाहब राम थे...

सांसद प्रतिनिधि देवेंद्र यादव ने वरिष्ठ पत्रकार अनिल यादव को याद करते हुए उनके सेवाभावी कार्य बताए। उन्होंने कहा, आज मेरे बड़े भाई की 71वीं जयंती है। भाईसाहब को जो लोग ज्यादा जानते थे, उनमें एक मैं भी हूं। वे मेरे दोस्त थे तो पिता भी। उन्होंने परिवार को बांधे रखा। उन्होंने अपने जीवन में परिश्रम किया और बुलंदियों पर पहुंचे। वे मेरे हीरो थे। वे राम थे तो मैं लक्ष्मण। जो उन्होंने कहा, मेरे लिए शिरोधार्य रहा। भाभी (शशि यादव) के रूप में हमें लक्ष्मी मिलीं, जो आज भी परिवार को जोड़े हैं। भाईसाहब की स्मृति को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए हम अनेक कार्य कर रहे हैं, उसी के अंतर्गत यह पत्रकार भवन भी बनाया गया है।

इन्होंने कार्यक्रम को किया संबोधित

महंत राममनोहर दास, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र मोहन शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता अतुल शाह, वरिष्ठ पत्रकार डीपी शर्मा, पूर्व विधायक एवं पत्रकार निशंक जैन, भाजपा नेता सुधीर यादव, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सक्सेना, पर्यावरण विद् श्याम बोहरे, वरिष्ठ पत्रकार गोविंद नायक, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश श्रीवास्तव ने संबोधित किया। मंच संचालन राष्ट्रीय कवि संगम के आशीष दुबे ने किया।

पत्रकारों का हुआ सम्मान

कार्यक्रम में भोपाल के वरिष्ठ पत्रकार उमेश त्रिवेदी, गिरीश उपाध्याय, मृगेंद्र सिंह, अजय बोकिल, जगदीश द्विवेदी, पंकज शुक्ला, सतीश एलिया, गुरेंद्र अग्निहोत्री, विदिशा के वरिष्ठ पत्रकार वेदप्रकाश शर्मा, अतुल शाह, सचिन तिवारी, आरके वसुदेव, बीडी अहिरवार, सिरोंज के अब्दुल शुबूर हसन, राजीव जैन, गुलाबगंज के ओपी खैरा, गंजबासौदा के डॉ.डीपी शर्मा, गोविंद नायक, कैलाश सक्सेना, सौदान सिंह यादव, यशपाल यादव, सत्यनारायण शर्मा, अखिलेश श्रीवास्तव, ओपी चौरसिया सहित कई वरिष्ठ पत्रकार गणों का सम्मान किया गया। लोकार्पण कार्यक्रम में राजेश तिवारी, निशंक जैन, सुरेंद्र दांगी, सुरेंद्र भारद्वाज, विजय अग्रवाल, राजेंद्र व्यास सहित नगर के अनेक गणमान्य जनों की उपस्थिति रही।

प्रेस क्लब के सदस्य रहे उपस्थित

कार्यक्रम में प्रेस क्लब महासचिव देवेन्द्र रघुवंशी, अखिलेश लाहौरी, प्रमोद राजपूत, उपाध्यक्ष आशीष रघुवंशी, राजा छारी, संजय शर्मा, मयंक टांक, सौरभ सक्सेना, सुरेन्द्र सिंह दांगी, रवि यादव, सह सचिव हरीश भावसार, देवेन्द्र राजपूत, नरेन्द्र नामदेव, सुरेन्द्र पस्तोर, शैलेन्द्र सक्सेना, अनुज यादव, मीडिया प्रभारी सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, गगन दुबे, रविकांत दीक्षित, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश चतुर्वेदी, घासीराम सेन, योगेश शिल्पकार, भूपेन्द्र नरवरिया, विजय रघुवंशी, एल.एन.चौबे, विजय रघुवंशी, कमलेश शर्मा, अमित शुक्ला, राहुल नामदेव, रिंकू रघुवंशी, यशवंत दुबे, रानू जैन, दीपेश जैन, सौरभ तामेश्वरी, बलराम अहिरवार सहित नगर के तमाम पत्रकारगण उपस्थित रहे।

ये मेरे लिए गर्व के क्षण : शशि यादव

नगर पालिका अध्यक्ष शशि अनिल यादव ने कहा कि आज का दिन मेरे लिए शब्दों में बयां कर पाना आसान नहीं है। यह दिन मेरे लिए एक साथ गर्व, सम्मान और गहरे विषाद का क्षण है। आज जब मैं अपने जीवन के पथप्रदर्शक, मेरे जीवनसाथी, मेरे सखा, मेरे मार्गदर्शक स्वर्गीय श्री अनिल यादव जी को स्मरण कर रही हूं तो लगता है मानो समय एक पल को ठहर गया है। उनके साथ बीते हर लम्हे की छवि मेरे सामने चलचित्र की तरह बह रही है। वे मेरे संबल थे, मेरी प्रेरणा थे। उन्होंने जिस तरह अपने विचारों, अपने शब्दों और अपनी कर्मठता से समाज को दिशा दी, वह अपने आप में अद्भुत अध्याय है। वे पत्रकार थे, लेकिन पत्रकारिता उनके लिए सिर्फ एक पेशा नहीं था, वह तो उनका जुनून था, उनकी आत्मा थी। वे शब्दों में सिर्फ खबरें नहीं लिखते थे, वे उन शब्दों से समाज की नब्ज को छूते थे, उसमें चेतना का संचार करते थे। वे पर्यावरण के प्रहरी थे। पेड़-पौधों से लेकर वन्य जीवन तक, हर उस चीज की चिंता उन्हें थी, जिसे हम आमतौर पर अनदेखा कर देते हैं। जंगल की खामोशी में वे विकास की आवाज सुनते थे, नदियों की धारा में वे जीवन की ऊर्जा देखते थे, पक्षियों की चहचहाहट में उन्हें भविष्य की उम्मीद दिखती थी। कितने ही युवाओं को उन्होंने न सिर्फ पत्रकार बनाया, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति जिम्मेदार नागरिक भी बनाया। उन्होंने जीवनभर वंचितों की आवाज को अपनी कलम से ताकत दी। उन्होंने समाज के उन हिस्सों को मंच दिया, जिन्हें अक्सर मुख्यधारा भुला देती है...पारधी, बंजारे, लोहगड़िया, सपेरे अनिल जी की लेखनी में ये लोग कभी पराये नहीं थे। उन्होंने हमेशा अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को समाज के बीच सबसे आगे रखा। आज जब वे शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, तो भी उनका लिखा हर शब्द, उनकी कही हर बात, उनके बताए हर रास्ते सब कुछ मेरे और हम सभी के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। जब-जब मैं विचलित होती हूं, मुझे उनका धैर्य याद आता है। जब कोई कठिनाई सामने आती है, तो मुझे उनका साहस संबल देता है। जब कोई निर्णय लेना होता है, तो उनकी सीख रास्ता दिखाती है। उन्होंने सांसद प्रतिनिधि एवं अपने देवर देवेंद्र यादव के सेवाभावी कार्य बताते हुए कहा कि मैं सीता तो नहीं हूं, लेकिन मेरे देवर सचमुच लक्ष्मण हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने श्रीमती पटवा के जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं और आशीर्वाद प्राप्त किया

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय सुंदरलाल जी पटवा की धर्मपत्नी श्रीमती फूल कुंवर जी पटवा के 95वें जन्म दिवस पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दीं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधायक श्री सुरेंद्र पटवा के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचकर श्रीमती फूल कुंवर जी पटवा को पुष्पगुच्छ और शाल-श्रीफल भेंट किया तथा श्रीमती पटवा के स्वस्थ-सुखी जीवन और दीर्घायु होने की कामना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर आयोजित सुंदरकांड पाठ के लिए दीप प्रज्जवलित किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव का विधायक श्री सुरेंद्र पटवा के निवास पहुंचने पर पटवा परिवार द्वारा डॉ. यादव का तिलक कर स्वागत-अभिवादन किया गया।

महाविद्यालयों में पीजी प्रवेश के लिए बढ़ी अंतिम तिथि

अब विद्यार्थी 10 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन, 21 तक चलेगी सीट आवंटन प्रक्रिया

भोपाल (नप्र)। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पीजी) कक्षाओं में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को राहत दी है। उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए विभाग ने पीजी स्तर पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग राउंड (सीएलसी) के टाइम टेबल में बदलाव किया है। जिसके तहत ऑनलाइन पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन कर सकेंगे।

साथ-साथ चलेगा आवेदनों के दस्तावेजों का सत्यापन: नए टाइम टेबल के अनुसार, वे सभी विद्यार्थी जो सत्र 2025-26 में पीजी के मेजर-माइनर विषयों में, या मेजर और माइनर विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें 7 जुलाई से 10 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। इन विद्यार्थियों को साक्षात्कार के लिए दिनांक, स्थान और समय की सूचना 14 जुलाई को मिलेगी। इसके बाद, इन विद्यार्थियों के साक्षात्कार और उनके अंकों की पोर्टल पर प्रविष्टि 16 और 17 जुलाई को की जाएगी। यह चरण उन विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए है जिनमें प्रवेश हेतु साक्षात्कार आवश्यक होता है।

21 जुलाई को पूरी होगी आवंटन प्रक्रिया: सीट आवंटन की प्रक्रिया 21 जुलाई को पूरी की जाएगी। जब विद्यार्थियों को उनके संबंधित महाविद्यालयों में सीटों का आवंटन किया जाएगा।

मोहर्रम जुलूस में हिंदू राष्ट्र का बैनर जलाने का वीडियो

रतलाम के सैलाना में बाजार बंद, हनुमान चालीसा पाठ; चार आरोपी गिरफ्तार

रतलाम (नप्र)। रतलाम के सैलाना में मोहर्रम के जुलूस के दौरान एक घटना का वीडियो वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति बन गई। वीडियो में एक युवक मुंह में पेट्रोल भरकर आग को एक बैनर की तरफ फूंकता दिख रहा है। इस भगवा बैनर पर बड़े शब्दों में हिंदू राष्ट्र लिखा है। आग से बैनर आंशिक रूप से जल गया। घटना रविवार रात को मस्जिद चौराहे की है। वीडियो सोमवार सुबह वायरल हुआ। सर्व हिंदू समाज और अन्य धार्मिक-सामाजिक संगठनों ने घटना को जानबूझकर की गई हरकत बताया। इसे भगवा ध्वज का अपमान कहा। विरोधस्वरूप बाजार बंद रखा। हिंदूवादी संगठनों ने कहा- मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी ऐसा कर रहे युवक को नहीं रोका। उन्होंने आरोपी के खिलाफ रासुका (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल, पुलिस वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर रही है। एहतियातन इलाके में बल तैनात किया गया है।

पुलिस ने चार आरोपियों को किया गिरफ्तार: पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें मेडिकल के लिए पुलिस थाना से पैदल ही हॉस्पिटल ले जाया गया। चारों की हालत चलने लायक नहीं थी।

आरोपियों के नाम

- शहजाद पिता सलीम मेव निवासी कालिका माता रोड, सैलाना
- बबलू शाह निवासी कब्रिस्तान रोड, सैलाना
- भय्यु पिता मुन्ना खान पठान निवासी कालिका माता रोड, सैलाना
- अज्जू शाह पिता रमजानी शाह निवासी मस्जिद चौराहा, सैलाना
- सड़क पर बैठकर किया हनुमान चालीसा का पाठ
- घटना से गुस्साए लोगों ने मस्जिद चौराहे पर सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके पर एसडीओपी सैलाना नीलम बघेल, रतलाम ग्रामीण एसडीओपी किशोर पाटनवाला और थाना प्रभारी सुरेश गडरिया मौजूद रहे।

प्रयोगधर्मी भाजपा में 'मिथक' टूटा

भाजपा और उसके फैसलों को लेकर एक बड़ा मिथक चला आ रहा था - कि जो नाम चर्चाओं में होता है, वो कभी फैसले में नहीं आता। जैसे वो किसी गुप्त प्रयोगशाला में फैसले पकाते हों, और लीक हुई 'रेसिपी' को आखिरी मौके पर बदल देते हों। लेकिन ठहरिए! संगठन की 'प्रयोगशाला' वाले हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा ने इस बार अपना ही चौंकाने वाला मिथक तोड़ दिया है। भाई साहब, इस बार वो हो गया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी! जब सब हेमंत खंडेलवाल का नाम लेकर गपशप कर रहे थे और अंदरखाने कई 'कद्दावर' नामों पर दांव लग रहा था, तब पार्टी ने कमाल कर दिया। पता चला कि खंडेलवाल जी की लो-प्रोफाईल छवि ने कमाल दिखाया। अब ये कहना कि 'इसकी चली' या 'उसकी चली' - सब बेमानी हो गया है। इस बार भाजपा को सत्ता, संगठन और समन्वय का 'त्रिकोण' कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया और कमाल की बात ये कि कोई खेमेबाजी भी नहीं दिखी। या तो खेमेबाजी इतनी गुप्त हुई कि पता ही नहीं चला, या फिर इस बार वाकई सबने 'संगठन हित' में मौन धारण कर लिया। जो भी हो, भाजपा ने बता दिया कि जब हम चाहें, तो अपने ही बनाए मिथक भी तोड़ सकते हैं। अब आप देखते रहिए अगला कौन सा 'मिथक' टूटने वाला है!

मोहन का मंत्रालय

आशीष चौधरी

किसे मिलेगा 'संस्कृति का प्रसाद'!

लगता है हमारे संस्कृति विभाग में 'संस्कृति' के साथ-साथ 'भाई-भतीजावाद की संस्कृति' भी खूब फल-फूल रही है! सुना है, अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ-साथ हमारे प्यारे लोक दल भी सीधे कार्यक्रमों में नहीं बुलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीच में अब 'दलालों का पैनल' फिर से बनेगा! वाह रे व्यवस्था! जब सीधे संपर्क से बात नहीं बन रही, और हुनर पहचान में नहीं आ रहा, तो क्यों न 'कमीशन' के खेल में थोड़ा और 'रंग' घोला जाए? अब कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने से पहले, इन नए 'संस्कृति दलालों' को प्रसन्न करना होगा। शायद यही 'नूतन भारत की नवीन संस्कृति' है, जहां टैलेंट से ज़्यादा 'कनेक्शन' बोलता है। तो तैयार हो जाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अब मंच पर नहीं, बल्कि 'डील की टेबल' पर असली खेल होगा!

..और अब ज़मीन पर !

मध्यप्रदेश के पावर कॉरिडोर में इन दिनों दो 'महाबली' अफसरों की आपसी जंग ज़ोरों पर है। आलम ये है कि इस सियासी खींचतान में उनकी हालत उस पुरानी कहावत जैसी हो गई है - 'आसमान से गिरे, खजूर पर लटके, और अब सीधे ज़मीन पर आ गिरे!' सुनने में आया है कि दोनों अधिकारियों की कथित तौर पर एक-दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ ने न केवल उनके अपने पद को खतरे में डाला है, बल्कि प्रशासनिक गलियारों में भी 'ड्रामा' बढ़ गया है। यह लड़ाई इतनी तेज है कि इसका असर फाइलें खिसकने से लेकर जनहित के कार्यों तक पर पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जब धूल बैठेगी, तो कौन खड़ा रहेगा और कौन सियासी ज़मीन पर बिखरा मिलेगा। लोगों का तो यहां तक कहना है कि इस खींचतान में विदा हुए एक अफसर को यह मौका वरदान बनकर लौटेगा।

जहां से चले वहीं आ गए

मध्य प्रदेश के एक सीनियर आईएएस अफसर पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तो यह अफसर लूप लाइन में थे और ऐसी लूप लाइन जहां पर यह माना जाता है कि यदि सत्ता परिवर्तन होता है तो सरकार लूप लाइन में पड़े अफसर को इनाम स्वरुप मलाईदार ओहदे पर भेजती हैं लेकिन इस सीनियर आईएएस अफसर की प्रोफाइल के चलते उन्हें दो दशक बाद भी मलाईदार पद नसीब नहीं हुआ है और वह दो दशक बाद भी फिर उसी संस्था में पहुंच गए हैं जहां पर रहते हुए उन्हें यह उम्मीद थी कि भाजपा सरकार आएगी तो उन्हें एक वजनदार पोस्टिंग मिलेगी। हालांकि इस दौरान वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को एक दो पोस्टिंग जरूर ठीक-ठाक मिली लेकिन खराब प्रदर्शन के चलते उन्हें वहां से हटा दिया गया। बता दे कि उक्त वरिष्ठ आईएएस अफसर के प्रदर्शन को लेकर पूरी इस लाबी का मत एक जैसा ही है।

और खूब छलके जाम !

राजधानी के पाश इलाके में मौजूद एक रेस्ट हाउस में बीती रात अखिल भारतीय सेवा के एक अफसर के जन्मदिन कम विदाई पार्टी में बारिश की बौछारो के बीच जमकर जाम छलके। अधिकारी के जन्मदिन और इसी माह शासकीय सेवा से सेवानिवृत होने के उपलक्ष्य में सभी जूनियर अधिकारियों ने पार्टी में जमकर एंजॉय किया। देर रात तक अधिकारियों की महफिल में जाम भी छलके। बता दे कि अधिकारी जंगल महकमा के हैं।